राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका

वर्ष-12, अंक-05, अगस्त 2025

₹ 20/- पेज-52

राष्ट्र समाज

आपकी आवाज़

भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह गति सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की भावना से हासिल की गई है। पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 10वें स्थान से बढ़कर पहले शीर्ष पांच में पहुंच गई है और अब तेजी से शीर्ष चार से शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है।

भारत की नई बुलंद तस्वीर

सकरनी® पेन्ट
रंग ऐसे
जो रंग जमा दें!
हर घर का
कंप्लीट सलूशन
सकरनी UNIVERSAL STAINER
SAK CLASSIC
सकरनी प्राइमर Magic Grip
सकरनी डिस्टेंपर पेन्ट SUPER SHINE
सकरनी इमल्शन पेन्ट QUICK CLEAN
सकरनी इमल्शन पेन्ट CHARM
CHARM GOLD
सकरनी प्राइमर PRO PROTECT
Badalte Bharat Ka
Shilpkaar
SAKARNI PLASTER (INDIA) PRIVATE LIMITED
D Mall 405, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034
customercare@sakarni.com | +91-9810177365 | www.sakarni.com

प्रमोद तिवारी

राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का समय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर अतिरिक्त २५ फीसदी टैरिफ लगाने के बाद कुल टैरिफ अब 50 प्रतिशत हो गया है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के जवाब में उठाया गया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका के सबसे अधिक कर वाले व्यापारिक साझेदारों में से एक बन गया है। अतिरिक्त २५ फीसदी टैरिफ २७ अगस्त से प्रभावी होगा। इस वृद्धि से अमेरिका को 40 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के भारतीय निर्यात प्रभावित होंगे, जिनमें ऑटो पार्ट्स, कपड़ा और परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात और रसायन, आभूषण और समुद्री खाद्य आदि शामिल हैं।

कुछ क्षेत्रों को टैरिफ वृद्धि से छूट भी दी गयी है, जिनमें फार्मास्युटिकल्स, स्मार्टफोन और लैपटॉप, सेमीकंडक्टर जैसे तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल, गैस और एलएनजी, तांबा इत्यादि ऊर्जा उत्पाद हैं। यदि अमेरिकी टैरिफ प्रभावी होंगे, तब भी अमेरिका को भारत का निर्यात अधिकतम 5.7 अरब डॉलर ही गिरेगा। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि २०२१ और २०२4 के बीच भारत को रूस से तेल आयात करके ३३ अरब डॉलर का फायदा हुआ। यानी यदि नफा-नुकसान देखें, तो भारत को रूस से तेल आयात से इतना फायदा है कि उसे अमेरिकी टैरिफ की परवाह करने की जरूरत नहीं।

भारत स्वाभाविक रूप से रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता बढ़ाने के लिए रक्षा उपकरण खरीदने और जहां से भी कच्चा तेल मिले, उसे सबसे सस्ते दामों पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि घरेलू मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना रहे। इस बीच भारत सरकार की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि अगर अमेरिका सोचता है कि वह इस तरह की धमकियां देकर हमारे देश को दबा सकता है।

वास्तविकता यह है कि भारत स्वाभाविक रूप से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए रक्षा उपकरण खरीदने और जहां से भी कच्चा तेल मिले, उसे सबसे सस्ते दामों पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि घरेलू मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना रहे। इस बीच भारत सरकार की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि अगर अमेरिका सोचता है कि वह इस तरह की धमकियां देकर हमारे देश को दबा सकता है, तो उसे अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है। आज का भारत एक दशक पहले जैसा नहीं है। हम हथियार उत्पादन में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने दुनिया को दिखा दिया है कि सामरिक दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हैं।अमेरिका को समझना होगा कि विश्व अब एकध्रुवीय नहीं रह गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने ऐसे समय में एक रणनीतिक साझेदार के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने का फैसला किया है, जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चीन द्वारा व्यापार और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के हथियारीकरण से उत्पन्न कहीं अधिक बड़ी चुनौती का सामूहिक रूप से जवाब देने की जरूरत है। भारत सरकार वास्तव में बधाई की पात्र है कि भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता के दौरान दबाव के बावजूद दृढ़ता से खड़ी है। पारस्परिक शुल्कों की धमकियों और नौ जुलाई और ३१ जुलाई की समयसीमा चूक जाने के बावजूद भारतीय वार्ताकारों ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) कृषि उत्पादों, डेयरी आयात और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के लिए हमारे बाजारों को जबरन खोलने के प्रयासों का सही ढंग से विरोध किया है।

राष्ट्र समाज

वर्ष-12, अंक-05, अगस्त 2025

RNI No.: DELHIN/2014/56304 ₹20

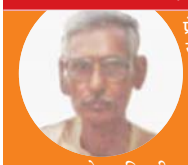

प्रेरणा स्त्रोत

स्व. पुरुषोत्तम तिवारी

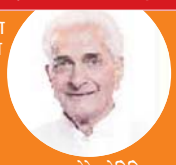

स्व. एनके लोहिया

मुख्य संरक्षक
विनीत कुमार गुप्ता

संरक्षक
बालमुकुन्द ओझा, त्रिवेणी नाथ तिवारी, हरिशंकर दुबे, संजीव गोयल

संपादक
प्रमोद तिवारी

सह संपादक
अवधेश शास्त्री (धर्म समाज)
सुशील ओझा (अर्थ समाज)

सलाहकार मंडल
हरिशचंद्र मिश्रा, अशोक (सकरनी)
ऋषि मित्तल, दिलबाग खंडूजा

ब्यूरो चीफ
पुनीत मिश्रा, अखिलेश शर्मा, मोहम्मद तैयब खान, अशोक शर्मा, श्यामल सिन्हा

कानूनी सलाहकार
अधिवक्ता बीपी पाण्डेय, गौरव भारद्वाज

प्रसार
पुनीत मिश्रा
9911882767

विज्ञापन
कृष्ण गोपाल मिश्रा
9899819135

डिजाइन व प्रोडक्शन
एनएम मीडिया सॉल्यूशंस, दिल्ली

संपादकीय कार्यालयः मकान नं. 2, हपली मंजिल, पश्चिम एन्क्लेव, रोहतक रोड, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087

दूरभाषः 011-40105158, 9953772767

ई-मेलः rastrasamaj@gmail.com

स्वत्वाधिकारी अपराइट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक प्रमोद तिवारी द्वारा एस-561, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-2, नई दिल्ली-84 से प्रकाशित तथा मित्तल इण्टरप्राइजेज 2016 गोकुल शाह स्ट्रीट सीता राम बाजार दिल्ली-06 से मुद्रित।

***संपादकः प्रमोद तिवारी**

लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित

नोटः पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है, तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय में ही किया जायेगा। राष्ट्र समाज पत्रिका में प्रकाशित सभी पद अवैतनिक हैं। पत्रिका के लिए भेजी गयी सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व अनुबंध के बिना कोई भी पारिश्रमिक देने की व्यवस्था नहीं है।

इस बार

06 भारत को शेर बनाने की संघ की कवायद

08 भारत की नई बुलंद तस्वीर

12 भविष्य के युद्धों के लिए तैयार होती भारतीय सेना

14 हिन्दू या भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता

18 विपक्ष की लोकतंत्र पर चिंता या सत्तालोभ की राजनीति ?

20 मतदाता सूची मामले में देश को गुमराह कर रहा विपक्ष

22 केशव मौर्य के सहारे ओबीसी दांव

24 बिहार में पूर्वी भारत के विकास की अंगड़ाई

30 ठाकरे भाइयों ने महाराष्ट्र में समाज को भाषा के नाम पर बांट दिया

32 भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौताः एक क्रांतिकारी कदम

36 स्कूल छोड़ती बेटियांः संसाधनों की कमी या सामाजिक चूक ?

38 दुनिया की लाखों जिंदगियां में जहर घोलता अकेलापन

46 झारखंड आंदोलन के अमर नायक का युगांत

48 एक्टिंग छोड़ेंगी दीपिका पादुकोण

भारत को शेर बनाने की संघ की कवायद

संजय सक्सेना

भारत को फिर से सोने की चिड़िया नहीं, बल्कि शेर बनाना है यह संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने केरल की धरती से दिया है। जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही थी, उसी वक्त कोच्चि में भागवत ने शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ज्ञान सभा में मंच से जो कहा, उसका मतलब सिर्फ शिक्षा तक सिमटा नहीं रह गया। असल में यह आने वाले विधानसभा चुनावों से लेकर पाकिस्तान को चेतावनी तक, हर जगह एक नई लय जोड़ता नजर आता है। संघ प्रमुख ने साफ कर दिया कि अब भारत को ताकतवर बनना होगा क्योंकि दुनिया सिर्फ शक्ति की भाषा समझती है। यह बात ऐसे दौर में कही गई है जब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश ने फिर से दिखा दिया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में अब कोई समझौता नहीं होगा। पहलगाम में हमलावरों को जिस तरह सुरक्षा बलों ने घेरकर मार गिराया, उससे सरकार का आत्मविश्वास संसद में भी झलका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि देश के बड़े लक्ष्य पर ध्यान रखें, छोटे मुद्दों में उलझकर सैनिकों के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।

मोहन भागवत ने इस मौके पर मैकाले की शिक्षा नीति का जिक्र कर यह भी समझा दिया कि भारत को अपनी परंपरा और संस्कृति से कटकर कभी ताकतवर नहीं बना जा सकता। उनका कहना था कि हमें शिक्षा को सिर्फ रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि यह समाज निर्माण और सेवा भाव को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। संघ हमेशा से ही शिक्षा में भारतीय मूल्यों के समावेश पर जोर देता रहा है। लेकिन इस बार बात महज शिक्षा सुधार तक नहीं रुकी, भागवत ने साफ कर दिया कि भारत की पहचान भारत ही रहनी चाहिए। उन्होंने भारत बनाम इंडिया की बहस में दखल देते हुए कहा कि इंडिया दैट इज भारत ठीक है, लेकिन भारत का अनुवाद नहीं होना चाहिए। ये बात विपक्ष के उस इंडिया गठबंधन के लिए भी सीधा संदेश है जिसने नामकरण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे।

भागवत ने कहा कि जब हम लिखते-बोलते हैं तो भारत को भारत ही कहना चाहिए, यही असली सम्मान है। साफ है कि ये बातें सिर्फ किताबों में छपने के लिए नहीं बोली गईं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देशभक्ति का माहौल बना है, उसे कायम रखना बीजेपी के लिए जरूरी है। आने वाले विधानसभा चुनावों में खासकर बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी को इसी राष्ट्रवादी हवा की जरूरत होगी। पहलगाम एनकाउंटर के बाद संसद में जब सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के अगले कदमों पर चर्चा कर विपक्ष के तीखे सवालों को दरकिनार किया, तो संदेश साफ था कि अब आतंकवाद को अंदर तक घुसकर खत्म किया जाएगा। अमित शाह ने संसद में कहा कि ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। यानी अब कोई नर्म नीति नहीं। ऐसे में मोहन भागवत का भारत को शेर बनाने वाला बयान वही माहौल और मजबूत करता है।

संघ को भी पता है कि राष्ट्रवाद का एजेंडा हर बार अपने आप नहीं चलता। कई बार महंगाई, बेरोजगारी और जातिगत समीकरण से बात बिगड़ जाती है। बिहार में जाति जनगणना की बात को लेकर संघ पहले से ही असहज है क्योंकि ये मुद्दा हिंदुत्व के नैरेटिव को कमजोर करता है। इसलिए भागवत ने एक और लाइन जोड़ दी कि कट्टर हिंदू होने का मतलब दूसरों से नफरत करना नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का सार तो सभी को गले लगाने में है। अक्सर लोग समझते हैं कि कट्टर हिंदू मतलब दूसरे धर्मों को गाली देना, लेकिन यह गलतफहमी है। संघ प्रमुख की इस समझाइश से साफ है कि वो बीजेपी को यह रास्ता दिखा रहे हैं कि हिंदुत्व के कड़वे चेहरे को थोड़ी नरमी से पेश किया जाए ताकि नए वोटर भी जुड़ सकें।

केरल में यह बात कहना भी अपने आप में बड़ा संदेश है क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी को अब भी बाहरी पार्टी माना जाता है। लेकिन संघ पिछले कुछ वर्षों से दक्षिण में लगातार सक्रिय है। केरल में खासकर ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक को साधना आसान नहीं है, लेकिन शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे ऐसे हैं जिनके जरिए जमीन पर धीरे-धीरे पकड़ बनाई जा सकती है। यही वजह है कि कोच्चि से लेकर कोयंबटूर तक संघ के कई संगठनों ने शिक्षा सम्मेलन से लेकर स्वास्थ्य शिविर तक का सहारा लिया है

ताकि जमीनी जुड़ाव बने।

मोहन भागवत के ताजा बयानों से बीजेपी को यह भी मदद मिलेगी कि जब नेता चुनावी मंचों से 'हाउ इज द जोश?' पूछेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर और शेर वाला नैरेटिव वोटरों के मन में ताजा रहेगा। पहलगाम का एनकाउंटर, संसद की गरमा-गरम बहस और संघ प्रमुख का शेर वाला संदेश ये तीनों मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव आते-आते विपक्ष के जातीय समीकरण या बेरोजगारी जैसे सवाल राष्ट्रवाद के शोर में दब जाएं।

बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट तो खैर संघ के बिना चलता ही नहीं। लेकिन हर बार संघ सड़कों पर दिखकर नहीं बल्कि चुपचाप गांव-कस्बों में मतदाता सूची खंगालने, बूथ लेवल कैडर मजबूत करने और संदेश पहुंचाने में लगा रहता है। ऊपर से भागवत जैसे बयान उस कैडर को दिशा देते हैं। जमीन पर कार्यकर्ता जब लोगों को समझाता है कि भारत अब शेर बन गया है और अब कोई भी दुश्मन सीमा पार से हमला नहीं कर पाएगा तो वोटर को भरोसा होता है कि मजबूत सरकार जरूरी है। ऐसे में आने वाला साल बीजेपी के लिए बड़ा है। बिहार चुनाव की तैयारी, बंगाल में पकड़ मजबूत करना और तमिलनाडु में नई जमीन तलाशना इन तीनों के बीच ऑपरेशन सिंदूर की गूंज और मोहन भागवत की शेर वाली लाइन जैसे तुरुप के पत्ते हैं। यही कारण है कि संसद से लेकर पंचायत तक बीजेपी की स्क्रिप्ट तैयार है भारत अब बुद्ध का देश तो रहेगा, लेकिन कमजोर नहीं रहेगा। यही लाइन विपक्ष के जातीय गठजोड़ों पर भारी पड़ सकती है।

कुल मिलाकर मोहन भागवत का केरल दौरा, संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा और पहलगाम में आतंकियों के खात्मे की खबर तीनों बातें एक ही कड़ी में बंध जाती हैं। भारत अब सोने की चिड़िया नहीं, शेर बनेगा और इस शेर की दहाड़ चुनावी मैदान तक पहुंचाई जाएगी। यही संघ की रणनीति है, यही बीजेपी का प्रचार मंत्र बनने वाला है। यही वजह है कि कोच्चि से उठी आवाज दिल्ली से लेकर दरभंगा तक गूंजेगी भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। यही बात जनता को याद दिलाई जाएगी और यही बात 2025-26 के चुनावी नतीजों में कितनी असर डालेगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

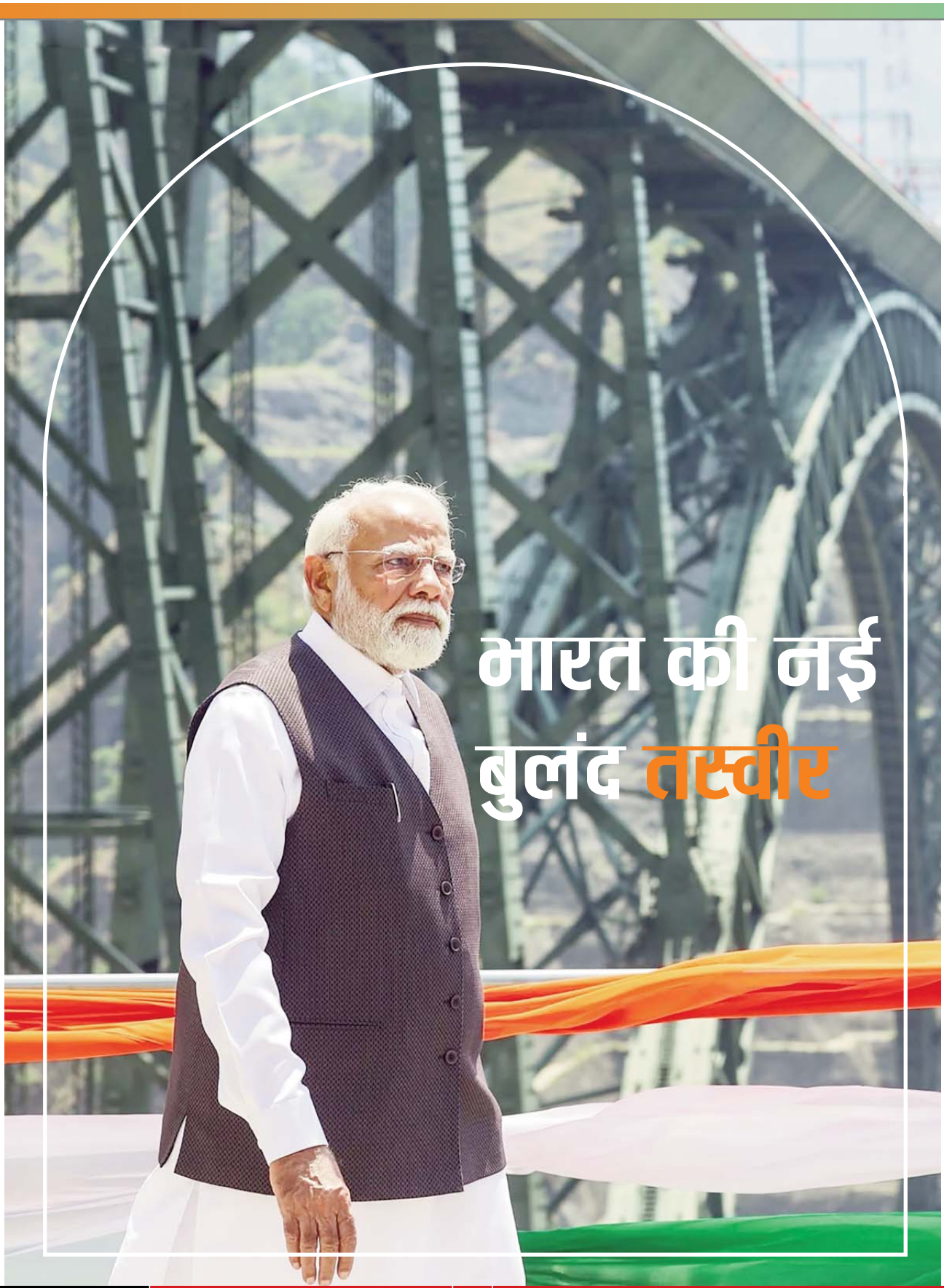

भारत की नई बुलंद तस्वीर

कमलेश पांडेय राष्ट्र समाज

दुनिया के आर्थिक और सैन्य मंच पर तेजी से कद्दावर बन चुके गुटनिरपेक्ष देश भारत ने रूस को साधकर नम्बर वन अमेरिका और नम्बर टू चीन को रणनीतिक मुश्किल में डालते हुए भींगी बिल्ली बना दिया है। इससे समकालीन विश्व के जी-7, नाटो, जी–20, ब्रिक्स और एससीओ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ग्लोबल साउथ की पूछ-परख बढ़ गई है, क्योंकि इनका अगुवा अब भारत बन चुका है। जानकार बताते हैं कि अमेरिकी दांवपेंचों और चीनी पैंतरों से आजिज आ चुके इन ग्लोबल साउथ के देशों को भारत की सदाशयी नीतियों से जो नीतिगत राहत और वैश्विक सहयोग मिला है, वह इनकी प्राथमिक जरूरत भी है। चूंकि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत सबसे तेज इकॉनमी बन चुका है, मजबूत सैन्य ताकत के रूप में छा चुका है, इसलिए भारत की मुखालफत दुनियावी थानेदारों को भी भारी पड़ सकती है।

यह ठीक है कि सीजफायर और टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दावों-आरोपों का भारत ने अभी तक जो भी जवाब दिया, उसमें भाषा विनम्र और सांकेतिक रखी गई। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। लेकिन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने गत दिनों जो ठोक-पीटकर जोशीला राजपूती बयान दिया है, इसके कूटनीतिक और राजनीतिक मायने में बिल्कुल अलग और अहम हैं। ऐसा इसलिए कि ट्रंप का नाम भी उन्होंने नहीं लिया, लेकिन इस बार जवाब ज्यादा सख्त था। रक्षा मंत्री सिंह के तल्खी भरे बयान यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अब भारत अपने राष्ट्रीय, मित्रगत और पड़ोसी हितों से कोई समझौता नही करेगा और जो इस रास्ते में अड़चनें पैदा करने की कोशिश करेगा, या वैसी ताकतों को शह देगा, उससे सख्ती पूर्वक ही निपटा जाएगा। इस बार सीजफायर वाली हड़बड़ाहट भी नहीं दिखाई जाएगी। इसलिए अब कोई भी बातचीत बराबरी के स्तर पर ही होनी चाहिए। वो भी अमेरिका-चीन जैसे देशों के साथ अनिवार्य तौर पर। लिहाजा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने ठीक ही कहा है कि नया भारत शेर की तरह दहाड़ता है। शक्तिशाली नेताओं की आंखों में देखकर बात करता है।

उल्लेखनीय है कि भारत के साथ अपने मनमाफिक डील करने में नाकाम रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत की इकॉनमी को ही 'डेड' बताया था। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी इसी निकृष्ट मानसिकता का दबंग अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे दबंग और गतिशील अर्थव्यवस्था करार दिया। जबकि 'सबके बॉस तो हम है' का भाव रखने वाले कुछ देशों को भारत का तेजी से विकास रास नहीं आ रहा है। समझा जाता है कि भारत से होने वाले आयात पर अमेरिका के 50 प्रतिशत टैक्स लगाए जाने के बाद उनका यह बयान सामने आया है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि हमारी चीजें बाहर महंगी हो जाएं। फिर भी कोई ताकत दुनिया की बड़ी शक्ति बनने से भारत को नहीं रोक सकती है। तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की है तो वह हमारे भारत की है। अब भारत 24000 करोड़ का रक्षा उत्पाद दुनिया को निर्यात कर रहा है। अब हमने भी ठान लिया है कि आतंकियों को उनके धर्म देखकर नहीं, बल्कि उनका कर्म देखकर मारेंगे। जो हमें छेड़ेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं।

यह महज संयोग नहीं कि रविवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की अर्थव्यवस्था पर बात की और भारत की अर्थव्यवस्था के तेज रफ्तार के बारे में संकेत देते हुए साफ कहा कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह गति सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन की भावना से हासिल की गई है। पिछले 11 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 10वें स्थान से बढ़कर पहले शीर्ष पांच में पहुंच गई है और अब तेजी से शीर्ष चार से शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था पर निशाना साधने के कुछ दिन बाद पीएम की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम ने यहां तक कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता के पीछे भारतीय टेक्नॉलजी और मेक इन इंडिया का हाथ था। उसने कुछ ही घण्टों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते ही भारत की जीडीपी ग्रोथ का 2025-26 के लिए अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखा, जबकि दुनिया की बाकी इकॉनमी की ग्रोथ के लिए यह अनुमान तकरीबन 3 फीसदी ही है।

वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएम

एफ) के डेटा बताते हैं कि 2024 में भारत ने ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में लगभग 17 प्रतिशत का योगदान दिया और अगले 5 साल में यह आंकड़ा 20 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इस तरह से कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने सबसे शानदार रिकवरी की और दुनियावी युद्धों व वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी वह बढ़त बनाए हुए है। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय विकसित अर्थव्यवस्था की हकीकत यह है कि खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय संकट के दौर में गुजर रही है। वहां पर ट्रंप की अव्यवहारिक नीतियों के चलते महंगाई दर बढ़ने का डर है, जिससे आर्थिक विकास दर पर बुरा असर होगा। ऐसा अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का भी मानना है। समझा जाता है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण अगर अमेरिका में मंदी के हालात बनते हैं, तो इसका असर दूसरे मुल्कों पर भी होगा।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि ट्रेड और टैरिफ पर ट्रंप का सख्त रुख किसी के लिए भी सही नहीं है। अब तो इसे टैरिफ टेरर या टैरिफ फतवा तक करार दिया जाने लगा है। आखिरकार इस बढ़े टैक्स की कीमत अमेरिकियों को ही चुकानी पड़ेगी। ऐसे में बेहतर है कि समाधान बातचीत से निकाला जाए। लेकिन, वह बातचीत एकतरफा और अपनी मर्जी थोपने वाली नहीं हो सकती। इसलिए अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भारत की एनर्जी संबंधी जरूरतें अमेरिका से

चीन पर भरोसा करके फिर रिस्क क्यों उठा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी?

बीते महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन की यात्रा पर थे। उन्होंने राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ मुलाकात में इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से पीएम मोदी और चिनफिंग के निर्देशन से द्विपक्षीय संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। उसी चीन यात्रा के लिए ग्राउंड वर्क तैयार रहा करने के लिहाज से अहम थी। इससे पहले जून महीने में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ भी चीन का दौरा किया था। सवाल है कि इतने तल्खी भरे रिश्ते के बावजूद भी दोनों देश कैसे करीब आए तो जवाब होगा कि पिछले वर्ष रूस में मोदी-जिनपिंग की हुई मुलाकात के बाद द्विपक्षीय रिश्तों की बर्फ ही नहीं पिघली, बल्कि पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसा तात्कालिक जख्म भी मिला, जिससे अमेरिका-चीन दोनों बेनकाब हुए। इससे पहले बंगलादेश से भारत समर्थक शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया। भारत ने यहां भी आत्मघाती चुप्पी साधी, जिससे अमेरिका-चीन के हौसले बढ़े।

यह ठीक है कि गत 23 जुलाई को पांच साल के अंतराल के बाद भारत ने चीन के लिए टूरिस्ट वीजा की बहाली की। वहीं, इस साल की शुरूआत में कैलाश मानसरोवर पर सहमति बनने के बाद 26 अप्रैल को इसके शेड्यूल की घोषणा हुई। वहीं, अब सीधी फ्लाइट्स की बहाली को लेकर भी सकारात्मक चर्चा चल रही है। इन परिस्थितियों में हमारी स्पष्ट सोच है कि अमेरिका, रूस, चीन को बातचीत के टेबल पर स्पष्ट कर दिया जाए कि आसेतु हिमालय के भारत के पड़ोसी देशों, अरब देशों, आशियान देशों में कोई भी भारत विरोधी कदम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत गुटनिरपेक्ष देश ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ का अगुवा राष्ट्र भी है। यदि चीन सहमत हैं तो प्रेम के पींगे बढ़ाइए, अन्यथा फुलस्टॉप लगा दीजिए। ऐसा करना ही हमारे लिए आर्थिक और सैन्य दृष्टि से श्रेयस्कर होगा। इससे भारत-चीन की ब्रेक के बाद होने वाली लड़ाई भी थम जाएगी।

बिल्कुल अलग है।

इसी तरह, विशाल किसान व पशुपालक आबादी को लेकर भी भारत की कुछ स्वाभाविक चिंताएं हैं। लिहाजा किसी भी समझौते में इन पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। उनका संकेत पीएम मोदी, एचएम शाह और डीएम सिंह के सख्ती भरे फैसलों व बयानों की तरफ था, जिन्होंने रविवार को धूम मचा दिया।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नागपुर में ठीक ही कहा कि आज दुनिया में जो देश दादागिरी कर रहे हैं, वे ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास उन्नत तकनीक है। फिर भी उन्होंने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि, दुनिया झुकती है बस झुकाने वाला चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत को अपनी निर्यात बढ़ानी होगी और आयात घटाने होंगे। अगर हमारी अर्थव्यवस्था और निर्यात की दर बढ़ेगी, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा, जिनके पास अच्छी तकनीक और संसाधन हैं, वही दबदबा दिखा रहे हैं। अगर हमारे पास भी यह सब होगा, तो हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति दुनिया के कल्याण की सोच रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की कई समस्याओं का हल विज्ञान और तकनीक है, और यह ज्ञान ही शक्ति है। अगर भारत को विश्वगुरु बनना है तो हमें निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना होगा। गडकरी ने सुझाव दिया कि शोध संस्थान, आईआईटीज और इंजिनियरिंग कॉलेज देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर शोध करें, हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी शोध जरूरी है।

भविष्य के युद्धों के लिए तैयार होती भारतीय सेना

मृत्युंजय दीक्षित

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से ही भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर, स्वदेशी तकनीक से समृद्ध, सुदृढ़ व सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। भारतीय सेना को भविष्य की रक्षा चुनौतियों लिए इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि भूमि से लेकर वायु और समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाईयों तक अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। आज अति आधुनिक ड्रोन से लेकर अविश्वसनीय मारक क्षमता वाली मिसाइलों तक का निर्माण भारत में किया जा रहा है।

विगत दिनों ईरान-इजराइल के मध्य संघर्ष के बीच ईरान के शक्तिशाली व मजबूत परमाणु संयंत्रो को नष्ट करने की क्षमता न होने के कारण इजराइल को भी अमेरिका की शरण में जाना पड़ा था। ऐसी ही परिस्थतियों से बचने के लिए भारत अब बंकर ब्लस्टर बम बनाने की दिशा में भी अग्रसर है। वर्तमान समय में कुछ ही राष्ट्रों के पास बंकर ब्लस्टर जैसी सुविधा उपलब्ध है और जब भारत भी उस श्रेणी में आ जाएगा। जब भारत का यह स्वदेशी बंकर ब्लस्टर बम बनकर तैयार हो जाएगा तब हमारी अग्नि-5 मिसाइल दुश्मन के मजबूत ठिकानों और तहखानों को मिनटों में ध्वस्त करके वापस चली आएगी।

भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं संगठन

अग्नि 5 मिसाइल के दो नये एडवांस प्रारूप विकसित कर रहा है जिसमें प्रथम प्रारूप बंकर ब्लस्टर वॉरहेड या विस्फोटक ले जाने वाला होगा जो जमीन के भीतर 80 से 100 मीटर तक जाकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करेगा जबकि दूसरा प्रारूप विस्फोटक ले जाने वाला होगा। ये दोनों ही प्रारूप दुश्मन के डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और हथियार डिपो को ध्वस्त करके वापस लौट आएंगे। अग्नि -5 बंकर ब्लस्टर मिसाइल जमीन, सड़क और मोबाइल लांचर से दागी जाएगी। अग्नि-5 भारत की एक ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक निशाना लगा सकती है। इसकी रेंज 5 से 7 हजार किमी तक हैं ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। भारत का बंकर ब्लस्टर बम अमेरिकी बम से भी अधिक क्षमतावान बनाया जा रहा है।भारत की बंकर ब्लस्टर मिसाइल अमेरिकी बम से अधिक गहराई तक निशाना लगा सकती है। भारत को चीन और पाकिस्तान से पैदा हुए खतरे को देखते हुए ही इस प्रकार की मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है।

भारतीय नौसेना को मिला तमाल- इसी प्रकार ब्रहमोस मिसाइलों से लैस अब तक का सबसे घातक आधुनिक स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल अब भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है जिसके कारण अब समुद्र में भी भारत की ताकत बढ़ गई है। इस बहुददेशीय अतिआधुनिक युद्धपोत का जलावतरण रूस के केलिनिनग्राद में हुआ। नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल यह युद्धपोत हिंद सागर में तैनात होगा और पाकिस्तान से लगती सीमा पर निगरानी में भारत की सबसे बड़ी ताकत बन जायेगा। तमाल युद्धपोत विगत दो दशकों में रूस से प्राप्त क्रियाक श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला में आठवां युद्धपोत है। यह पूर्ववर्ती संस्करणों की तुलना में अधिक उन्नत है।

इसमें लंबवत प्रक्षेपित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें उन्नत 100 मिलीमी की तोप, मानक 30 मिलीमीटर गन क्लोज -इन हथियार प्रणाली के अलावा आधुनिक समय की प्रणाली अत्यधिक भार वाले टारपीडो तत्काल हमला करने वाले पनडुब्बी रोधी, रॉकेट और अनेक निगरानी एवं अग्नि नियंत्रण रडार तथा अन्य प्रणालियां शामिल हैं।

युद्धपोत का नाम तमाल देवताओं के राजा इंद्र की पौराणिक तलवार से लिया गया है। इसकी मारक क्षमता भी उसी तरह तेज, आक्रामक और निर्णायक है। इसका शुभंकर भारतीय पौराणिक कथाओं के अमर भालू जाम्बवंत और रूसी राष्ट्रीय पशु यूरेशियन भूरे भालू की समानता से प्रेरित है। तमाल युद्धपोत का निर्माण रूस के कैलिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में हुआ है और इसमें 26 प्रतिशत स्वदेशी उपकरण हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आखिरी युद्धपोत है जो विदेश में बना है अब ऐसा कोई भी युद्धपोत भारत में ही बनेगा जिसके बाद भारत की नौसेना की शक्ति और बढ़ जाएगी। इस युद्धपोत के कुशल संचालन व रखरखाव के लिए 250 नौसेना कर्मियों ने रूस में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह बहु मिशन युद्धपोत भारत के समुद्री हितों के क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरों से निपटने में सक्षम है।

भारत की नोसेना को एक और स्वदेशी युद्धपोत उदयगिरि का उपहार भी मिला है। इस युद्धपोत में सुपरसोनिक सतह से सतह से मार करने वाली प्रणाली लगी है। इसमें 76 मिमी गन, 30 मिमी और 12.7 मिमी की रैपिड फायर गन सहित डीजल इंजन और गैस टर्बाइन युक्त सीओडीजी प्रणाली है। इस 3900 टन वजनी और 125 मीटर लंबे युद्धपोत में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लैस हैं। यह देनों ही युद्धपोत भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं।

हिन्दू या भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता

राष्ट्र समाज

2004 से 2014 के मध्य पूरा भारत आतंकवाद से त्रस्त था। आये दिन होने वाले आतंकी बम धमाकों ने देश की जनता को भयभीत कर रखा था। ऐसे ही बम धमाकों की श्रृंखला में महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाकों में कम से कम छह लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। 17 वर्षों के बाद मालेगांव की घटना की आम और खास लोगों में चर्चा का एक विशिष्ट प्रयोजन है। तत्कालीन केन्द्र की कांग्रेस सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की सारी हदें पार करते हुये जहां एक ओर पाक प्रायोजित आतंकवाद पर ढुलमुल रवैया अपनाये रही वहीं दूसरी ओर मालेगांव बम विस्फोट पर हिंदू आतंकवादी का एक काल्पनिक कथानक रचकर उसे खूब प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास किया। बिना किसी सबूत के और बिना किसी जांच के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा अन्य हिन्दू संगठन से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार लिया गया जिनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टीनेन्ट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी अजय रहीरकर, सुधाकर द्विवेदी और सुधाकर चतुवेर्दी प्रमुख हैं। सत्रह वर्षों बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के विशेष न्यायालय ने 31 जुलाई 2025 को सभी सातों आरोपियों को ठोस सबूतों के अभाव में दोषमुक्त घोषित करते हुए बरी कर दिया।

मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले हिन्दू तथा सनातन विरोधी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की भगवा आतंकवाद की पूरी थ्योरी न्यायपालिक के प्रथम चरण में ध्वस्त हो गई है। अब न्यायालय के निर्णय पर राजनीति होना स्वाभाविक गतिविधि है। विशेष अदालत के फैसले ने इस तथ्य को पुनःप्रमाणित कर दिया है कि एक हिन्दू अथवा सनातनी कभी भी आतंकी नहीं हो सकता। यह फैसला बहुसंख्यक हिन्दू समाज तथा संत समाज को आनंदित करने वाला है वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला समूचा विपक्ष आज उसी तरह से रो रहा है जिस प्रकार वे अयोध्या में बाबरी विध्वंस के समय रोये थे। यह वही मुकदमा है जिसके

आधार पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भगवा आतंकवाद का एक पूर्णतः असत्य कथानक रचा और पूरे विश्व में सनातन धर्म को अपमानित करने की कोशिश की। साध्वी प्रज्ञा सहित सभी सात आरोपियां को एक नितान्त मनगढ़ंत आरोपों से अपनी असंबद्धता सिद्ध करने के लिये 17 वर्षों तक न केवल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी अपितु सतत मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी थी। एक महिला होने के नाते सर्वाधिक अत्याचार व अपमान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 9 साल जेल में रहते हुए सहना पड़ा था।

प्रज्ञा ठाकुर का संत से संसद तक का सफर- मध्यप्रदेश की भगवाधारी महिला संत प्रज्ञा सिंह ठाकुर को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार कर उन्हें पर आतंकवचादी बताया था। लेकिन इन्हीं आरोपों को अवसर में बदलते हुए वह भोपाल से बीजेपी की सांसद चुनी गई। जेल में रहते हुए उन पर 10 दिनों तक अपना अपराध स्वीकार करने सहित साजिश कताओं के नाम बताने के नाम पर अथाह अत्याचार किये गये जिस कारण उनका स्वास्थ्य भी बिगड गया था। किंतु प्रज्ञा ठाकुर जी ने अपना धैर्य, साहस व मनोबल नहीं खोया सभी आरोपी बराबर कहते रहे थे कि यह एक साजिश है और उन सभी को फंसाया जा रहा है। उन सभी के साहस और धैर्य ने हिन्दू-भगवा को आतंकवाद के अनर्गल आरोप से मुक्त करा दिया है। अब आज जाकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर व सभी सात अन्य आरोपी पूर्ण रूप स्वतंत्र हुए हैं हालांकि अभी पीडित परिवारों के वकील का कहना है कि वह सभी लोग मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे वही कुछ मुस्लिम परस्ती की राजनीति करने वाले लोग इस मामले में जनहित याचिका भी डालने जा रहे हैं किंतु महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि फिलहाल वह इस मामले को ऊपरी अदालत में नहीं ले जाएगी। वहीं कांग्रेस सहित मुस्लिम संगठन महाराष्ट्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार वह त्वरित गति से मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले को ऊपरी आदालत में लेकर चली गई इसी प्रकार उसे इस फैसले में भी करना चाहिए।

किंतु यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि इन सभी अरोपियों के जो 17 बहुमूल्य वर्ष व समय खराब हुआ है उसकी भरपाई कौन और कैसे कर पायेगा? यह जानना भी आवश्यक है कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी का जनक आखिर है कौन और इससे किसको लाभ होने वाला था। किसने इन सभी लोगां को आरोपी बनाने की कहानियां गढ़ी क्या अब उन सभी को न्यायपालिका, जांच एजेंसियों के कठघरे में खड़ा किया जाएगा। आखिर कौन है जो हिन्दुओं व भगवा को बदनाम करने के लिए साजिशें रच रहा था और फिर सबसे विषेष मालेगांव व समझौता एक्सप्रेस जैसे बम धमाके करवाने व फिर उन सभी तमाम घटनओं में साधु -संतों को गिरफ्तार करने की साजिषें कौन रच रहा था। निश्चित रूप से उस समय कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस -एनसीपी की सरकार थी। जब यह घटना घटी थी उस समय महाराष्ट्र में एनसीपी के आर आर पाटिल गृहमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस के गृहमंत्री शिवराज पाटिल थे। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोर्ट का फैसला आने के बाद कहा कि भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ने के लिए अब कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। भगवा आतांकवाद की थ्योरी का जन्मदाता एनसीपी नेता शरद पवार को ही माना जा रहा है और उनकी इस नीति को गृहमंत्री शिवराज पाटिल के बाद सुशील कुमार शिंदे, मध्यप्रदेश कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह व कमलनाथ और फिर उसके बाद गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने ही पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया।

कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि कुछ लोगां ने अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थ के कारण भगवा आतंकवद के झूठे मुददे को अपनी विकृत राजनीति का हथियार बनाया और पूरे हिंदू समुदाय और हिंदू धर्म को आतंकावाद से जोडने की नाकाम कोषिष की गईं और अब इन सभी साजिषों की परत दर परत उखड़ने लग गई है। इससे पूर्व समझौता एक्सप्रेस बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में स्वामी असीमानंद महाराज भी बरी हो चुके हैं इस प्रकार यह दूसरा बड़ा अवसर है जब कांग्रेस की भगवा आतंकवाद की

थ्योरी कोर्ट में ध्वस्त हे गई है ।कोर्ट का फैसला आते ही हिंदू संगठनों में आनंद व उत्साह का वातावरण देखा गया तथा सभी ने पटाखे दागकर व एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर विजय का उत्सव मनाया।

कोर्ट की अहम टिप्पणियां- इस पूरे प्रकरण में अपने अंतिम फैसले में कई ऐतिहासिक व गंभीर टिप्पिणियां करते हुए कहाकि, 'आतंकवद का कोइ रंग या धर्म नहीं होता। कोर्ट ने माना है कि कई लोगों के बयान उन्हें प्रताड़ित करके लिए गये हैं।' कोर्ट का फैसला आने के बाद अब हिंदू संगठनों की ओर से पी. चिदंबरम, दिग्विजय सिंह सहित उन सभी लोगों पर कार्यवाही करने की मांग की जा रही है जो सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा आतंकवाद की झूठी साजिश रच रहे थे। निश्चय ही हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव एक राजनैतिक साजिश है इसका उद्देश्य इस्लामा आतंकियों को खुश करना और वोट बैंक को महबूत करने रहना है। यही कारण है कि कांग्रेस राज में हिंदुओं को डराने-धमकाने के लिए बम धमाके होते रहते थे और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा करती थी। आज पूरे भारत से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। भगवा आतंकवाद के जनक तिलमिलाए हुए हैं। यही कारण है कि जब आज सरकार आतंकी ठिकानों पर चुन-चुनकर कार्यवाही करती है तब सेना व सराकर से यह विरोधी दल सबूत मांगने लगते हैं। अब होने लगे खतरनाक खुलासे मालेगांव पर कोर्ट का फैसला आने के बाद उस समय रची गई साजिश भी बेनकाब होने लगी है और पूर्व अधिकारी तक टीवी चैनलों पर आकर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए रची गई खुलासा करने लगे हैं। उस समय इस मामले में संघ के कुछ बड़े नेताओं को भी फंसाने की मंशा थीं जिसमें इंद्रेश कुमार का नाम सबसे चर्चित था।

मालेगांव विस्फोट कांड की जांच करने वाली टीम के एक सदस्य मकहबूब मुजावर ने खुलासा किया है कि उस समय एनआईए के एक अधिकारी ने वर्तमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के लिए बहुत बड़ा दबाव बनाया था। अंततः उन्हें अपनी नौकरी से भी समय पूर्व ही हाथ धोना पड़ गया था। मुजावर कहते हैं कि रामजी कालसंगरा और संदीप डांगे की जगह साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का

नाम डालकर एक फर्जी जांच शुरू की गई। उन्होंने कहाकि एक ''गलत व्यक्ति'' के द्वारा की गई गलत जांच का परिणम आज सामने आ गया है।

इस मामले में तो यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फंसाने की साजिश रची गई थी। वह तो भला हो कि इस पूरे झडे प्रकरण में सभी गवाह धीरे-धीरे मुकरते चले गये। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुआ बम धमाका एक सुनियोजित राजनैतिक साजिश का एक बहुत ही बड़ा और घटिया हिस्सा था जो अब धीरे-धीरे ही सही लगातार बेनकाब होता जा रहा है और सेकुलर ताकतें भी उसी प्रकार से बेनकाब होती जा रही हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आजकल हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व का नारा दिया है और उसकी आड़ में वह सनातन हिदू संस्कृति पर चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि राहुल गांधी एक बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत ही हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व का मुददा उठा रहे थे। राहुल गांधी कई बार हिंदू विरोधी बयानबाजी कर चुके हैं। एक खोजी पत्रकारिता करने वाली संस्था विकीलिक्स में दिए इंटरव्यू में उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथ की तुलना में हिंदू संगठनों को हिन्दुत्व के उभार को सबसे बड़ा खतरा बताया था। यह वही राहुल गांधी हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर चुके हैं। स्पष्ट है कि राहुल गांधी के नेतृत्त वाला इंडी गठबंधन पूरी तरह से हिंदू विरोधी है और सनातन के उन्मूलन में लगातार लगा रहता है लेकिन यह लोग भूल जाते हैं कि जो सनातन है वो शाश्वत भी है और कभी समाप्त नहीं हो सकता।

Balaji Traders

Our Other Brands

Ro Water Purifier

Apne ghar ko dijiye shuddh aur surakshit paani ka tohfa
RO purifier ke saath sehat ka vada

पानी ऐसा, जिस पर आप आँख मूंदकर भरोसा करें

Marketing & Manufacturers by Balaji Traders

- 100% Pure & Safe Water
- Advanced 7 Stage Purification
- Retains Essential Minerals
- Removes Bacteria & Viruses

Place your order : www.balajiwaterpurifier.com

विपक्ष की लोकतंत्र पर चिंता या सत्तालोभ की राजनीति?

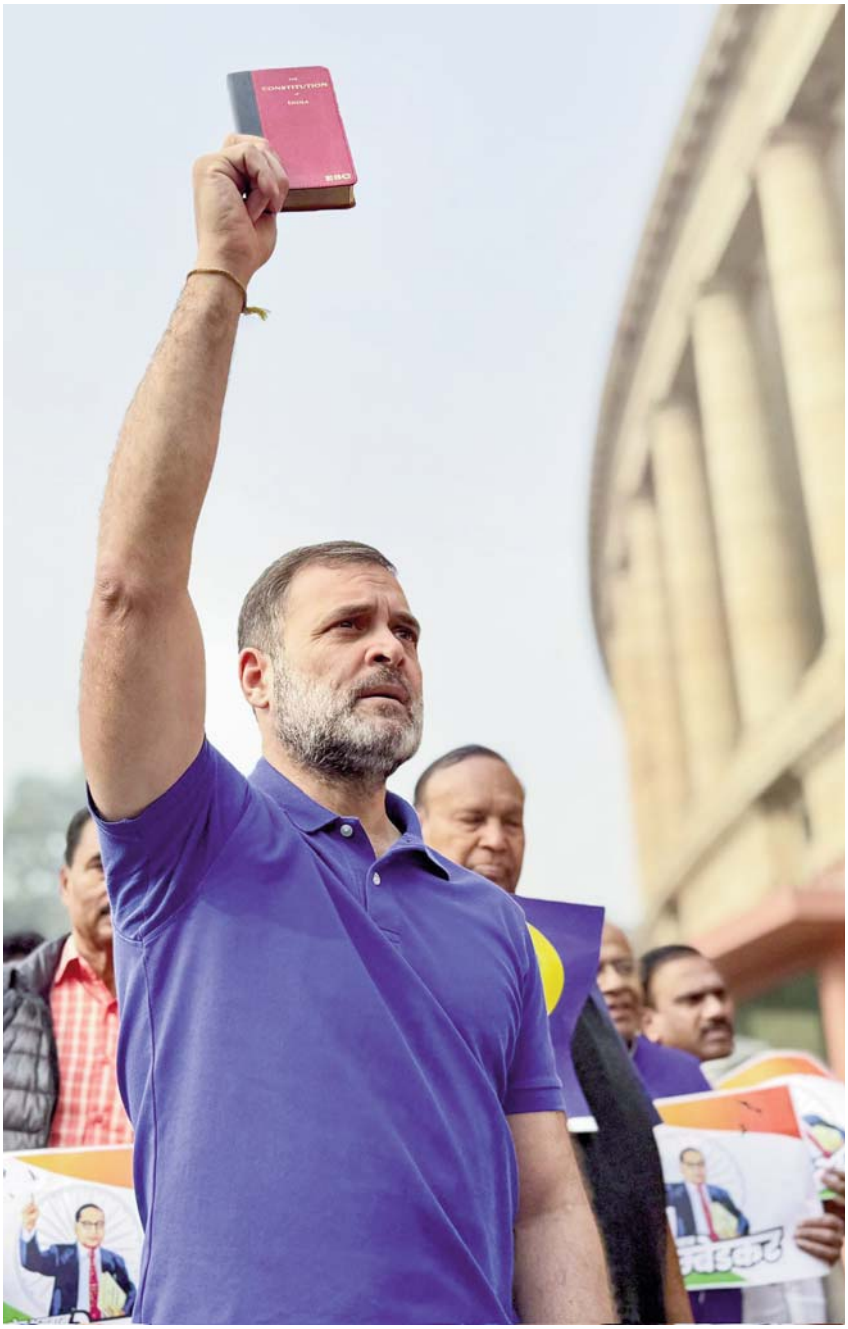

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र आज विश्व के सबसे बड़े, जीवंत और जागरूक लोकतंत्रों में गिना जाता है। यह संविधान की मजबूत नींव, संस्थाओं की पारदर्शिता और जनता की जागरूकता से संचालित होता है। परंतु विडंबना यह है कि देश का विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी, बार-बार लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की झूठी दुहाई देकर एक अनावश्यक और निरर्थक बहस छेड़ते रहे हैं, वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा को घेरने एवं दोषी ठहराने के लिये न केवल उन पर आधारहीन आरोप लगाते रहते हैं, वरन देश की संवैधानिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और संविधान के ही खतरे में होने का राग अलापते हुए उन्हें लांछित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नेता संविधान की दुहाई देते हैं, वे स्वयं संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। लोकतंत्र की आत्मा पर इस तरह का प्रहार विपक्ष की भूमिका पर एक बड़ा प्रश्न है। विडम्बना एवं चिन्ताजनक है कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं में भी मोदी-भाजपा का विरोध करते-करते देश-विरोध पर उतर जाते हैं, जिससे विदेशों में भारत की छवि का भारी नुकसान होता है और विदेशियों को लगता था कि भारत में लोकतंत्र और संविधान ढह रहा है।

नेता-प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उनके सहयोगी जब यह कहते हैं कि 'देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है', 'संविधान खतरे में है', तब यह केवल एक राजनीतिक शगूफा प्रतीत होता है, न कि कोई तर्कसम्मत आलोचना। यदि वास्तव में लोकतंत्र खतरे में होता, तो क्या वे हर मंच से खुलकर सरकार की आलोचना कर पाते? क्या संसद, मीडिया,

चुनाव आयोग, और न्यायपालिका जैसी संस्थाएं उनके वक्तव्यों को स्थान देतीं? असल में तो 1975 में लोकतंत्र एवं संविधान खतरे में आये थे जब तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने हेतु अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 'आंतरिक अशांति' के आधार पर आपातकाल लगाया तथा लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर हजारों नेताओं एवं बेगुनाह लोगों को कठोर कानूनों के अंतर्गत जेल भेज दिया। आजादी के बाद तब पहली और आखरी बार लोकतंत्र खतरे में आया था, तब संविधान भी खतरे में चला गया था।

राहुल गांधी अपने गिरेबान में झांकने एवं कांग्रेस के अतीत को देखने की बजाय मोदी-भाजपा पर लोकतंत्र एवं संविधान को खतरे में डालने का बेबुनियाद, भ्रामक एवं आधारहीन आरोप मंढते हैं। इन त्रासद स्थितियों में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा नहीं, बल्कि अपने खोए हुए जनाधार को पुनः प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। विशेषतः लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव-इनमें जरूरी एवं जनता से जुड़े विषयों को उठाने की बजाय लोकतंत्र एवं संविधान के खतरे में होने के राग से जनता को गुमराह करना आम बात हो गयी है।

देशभर में एवं अनेक राज्यों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार आदि के अवैध घुसपैठियें बड़ी मात्रा में घुस आये हैं। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिये इन घुसपैठियों को इन विपक्षी दलों की शह पर ही जगह मिल रही है, ये घुसपैठियें न केवल फर्जी तरीकों से आधार, पैन, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेज प्राप्त कर कई निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता-सूचियों में अपना नाम अंकित करा लिया है। यह लोकतंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनसंख्या संतुलन के लिए गंभीर खतरा है, चुनाव आयोग ने इस पर अपना रुख सख्त करते हुए सभी राज्यों में 'मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण' का निर्णय लिया है। बिहार में वह ऐसे लोगों की पहचान संबंधी पहल कर चुका है, पर विपक्ष को इस पर आपत्ति है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी। न्यायालय ने आयोग की इस कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई।

विपक्ष लम्बे समय से चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है, कभी निष्पक्ष मतदान पर तो कभी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर सवाल उठाते रहा है। चूंकि चुनाव ही सत्ता की सीढ़ी है, इसलिए लोकसभा चुनाव में परास्त होने और अनेक राज्यों में अप्रासंगिक होने से चुनाव आयोग पर आरोप तथा लांछन लगाना विपक्ष के लिए काफी आसान हो गया है। कभी वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों और निर्णयों पर अंगुली उठाता है, कभी उसे भाजपा के इशारे पर काम करने वाला बताता है, कभी ईवीएम, मतदाता सूची में अनियमितता, डाटा देने में विलंब, दलीय पक्षपात आदि का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग की छवि नष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को हरी झंडी देकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी।

विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में रचनात्मक आलोचना और वैकल्पिक नीतियों के माध्यम से शासन को दिशा देना होती है। किंतु आज का विपक्ष न तो पाकिस्तान-चीन के खतरनाक मनसूंबों, न गरीबी, न महंगाई, न बेरोजगारी, न सांप्रदायिक सौहार्द, न सीमा पर पड़ोसी देशों की चुनौती, और न ही किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याओं को लेकर कोई ठोस योजना प्रस्तुत कर पा रहा है और न ही इन बुनियादी मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा पा रहा है। उनकी राजनीति केवल मोदी और भाजपा विरोध तक सीमित होकर रह गई है। जब राजनीति 'विकास' की बजाय 'विरोध' पर केंद्रित हो जाए, तो वह जनहित नहीं, केवल सत्ता की भूख बन जाती है।

विपक्षी दल मोदी एवं भाजपा पर लगातार आक्रामक हैं। राहुल गांधी और अन्य दलों के नेता संविधान की प्रति लहराकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे संविधान खतरे में है और उन्हें उसे बचाना है। लेकिन भारत की जनता अब परिपक्व एवं समझदार हो गयी है, उसे अच्छा-बुरे में फर्क दिखता है। भाजपा पर 'तानाशाही', 'संविधान बदलने की साजिश', 'जनविरोधी नीतियों' जैसे आरोप लगाना विपक्ष की आदत बन चुकी है।

किंतु हर बार जनता ने चुनाव में स्पष्ट बहुमत देकर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जनता जानती है कि ऑपरेशन सिन्दूर, डिजिटल इंडिया, गरीबमुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, महिला आरक्षण, जी-20 की सफल अध्यक्षता, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, उन्नत सड़के, चमकती रेल एवं चमकते रेल्वे स्टेशन, घर, शौचालय और जल जैसी योजनाएं सिर्फ नारों से नहीं, संकल्प और समर्पण से संभव हुई हैं।

क्या राहुल गांधी या इंडी गठबंधन के पास कोई ठोस आर्थिक नीति, सुरक्षा रणनीति, या सामाजिक समरसता का ब्लूप्रिंट है? क्या वे यह बता सकते हैं कि वे भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, या केवल मोदी विरोध को ही नीति मान बैठे हैं? भारतीय जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुकी है। वह अब भावनात्मक और भ्रामक नारों के बजाय ठोस उपलब्धियों और दूरदर्शिता को प्राथमिकता देती है।

ऐसे में विपक्ष का यह दुष्प्रचार केवल उनकी साख को ही नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष को चाहिए कि वह सकारात्मक राजनीति करे, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करे, और जनता के विश्वास को अर्जित करे, न कि लोकतंत्र के अस्तित्व को ही संदेह के घेरे में लाकर अपनी विफलताओं पर पर्दा डाले। राजनीति केवल विरोध नहीं, समाधान का माध्यम होनी चाहिए।

मतदाता सूची मामले में देश को गुमराह कर रहा विपक्ष

डॉ. आशीष वशिष्ठ

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पूरा हो चुका है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक एसआईआर का विरोध जारी है। हालांकि विपक्ष के तीखे विरोध के बीच चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिर्फ असम में भाजपा सरकार है। शेष राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। वे अभी से चौकन्नी हो गई हैं और एसआईआर को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना देना चाहती हैं।

वास्तव में विपक्ष रणनीति के तहत एसआईआर पर देशवासियों को गुमराह कर रहा है। सड़क से संसद तक वो एसआईआर का विरोध कर रहा है, और चुनाव आयोग पर अमर्यादित बयानबाजी से लेकर आरोप तक लगा रहा है। जबकि तस्वीर का दूसरा पक्ष यह है कि बिहार में एसआईआर का विरोध कर रही पार्टियों ने भी अपने बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए को बढ़-चढ़कर काम में लगाया था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 23 जून को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के पहले कांग्रेस ने केवल 8586 बीएलए लगाए थे। लेकिन 25 जुलाई को प्रक्रिया समापन के वक्त कांग्रेस के 17549 बीएलए नियुक्त रहे। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने के बावजूद इसके लिए 105 फीसदी बीएलए बढ़ाए।

भाजपा के 53338 बीएलए प्रकिया का हिस्सा बने। राष्ट्रीय जनता दल के 47506 बीएलए प्रक्रिया में शामिल हुए। जनता दल यूनाइटेड के 36550 बीएलए शामिल हुए। लेफ्ट पार्टियों ने एसआईआर प्रक्रिया की शुरूआत में दिलचस्पी नहीं दिखाई लेकिन आखिर तक इन पार्टियों ने भी बीएलए की संख्या बढ़ाई। बिहार में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कुल 1 लाख 60 हजार 813 बीएलए गहन मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बने। किसी तरह की अनियमितता होने पर विपक्षी दलों के कार्यकर्ता तुरंत अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन अब तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया है जहां विपक्षी दलों के कार्यकताओं ने इसकी शिकायत की हो। केवल विपक्ष के नेता ही इस तरह की बात कर सनसनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का असली चेहरा और चरित्र यही है।

वो एक और देशवासियों को गुमराह करने और संवैधानिक संस्थाओं की साख को धूमिल करने का कुकृत्य करता है, तो वहीं दूसरी और कानून प्रक्रियाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेता है।

बिहार ही नहीं देशभर में फर्जी और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के मांग राजनीतिक दल समय समय पर उठाते रहे हैं। बिहार के सीमांचल के इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला वर्षों से सामने आ रहा है। पिछले 30 वर्षों में पूरे सीमांचल का समीकरण बदल गया है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में अल्पसंख्यकों की आबादी 40 फीसदी से 70 फीसदी तक हो चुकी है। यही कारण है कि वर्षों से इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों की रोक की मांग उठती रही है। कई इलाकों से हिंदुओं के पलायन की भी खबर उठी थी। केंद्र सरकार ने जब पूरे देश में एनआरसी लागू करने की बात कही थी तो बिहार में इस इलाके से भी विरोध के सुर उठे थे।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार के 99.8 फीसदी यानी 7.23 करोड़ मतदाता इस रिवीजन प्रक्रिया में कवर हो चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि पुनरीक्षण में बिहार में कम से कम 61 लाख मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। इसमें 21.6 लाख मतदाताओं का निधन हो चुका है। 31.5 लाख मतदाता स्थाई तौर पर दूसरे स्थानों-शहरों में बस गए हैं। हैं। लगभग सात लाख मतदाताओं के नाम दो स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज हैं।

बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। विधानसभाओं में कुछ सौ मतदाताओं का अंतर ही जीत-हार पर असर डाल देता है। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में करीब बीस प्रतिशत सीटों पर जीत और हार का अंतर महज ढाई फीसद तक ही था। इनमें से 17 सीटों पर जीत तो एक प्रतिशत के कम वोट से ही हुई थी। अगर गहन पुनरीक्षण में इन मतदातओं के नाम नहीं काटे गए तो उनके नाम पर चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव चुनाव बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं। हालांकि देश की राजनीति के लिए यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी राजनीतिक दल ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी हो। इससे पहले भी जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में अनेक बार कुछ राजनीतिक दलों और अतिवादी संगठनों ने चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी। आपातकाल के बाद भी प्रमुख विपक्षी दलों ने चुनाव के बहिष्कार करने की बात की थी। हालांकि इसके बावजूद वहां चुनाव हुए और उन सभी लोगों ने चुनाव में हिस्सा भी लिया और जीत हासिल की।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का मुद्दा अपनी स्टाइल में उठा रहे हैं। वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर 'वोटों की चोरी' का आरोप लगा रहे हैं। वोटिंग में गड़बड़ी का इल्जाम तो राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगाने लगे थे, लेकिन अब ज्यादा जोरदार तरीके से उसे उठा रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बाकी चुनावों के मामले चुप्पी साध लेते हैं।

राहुल गांधी पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग पर तल्ख, अमर्यादित और अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। आयोग पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। असल में राहुल गांधी चुनाव आयोग और चुनाव मशीनरी को दबाव में लेना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुले मंच से यह घोषणा कर चुकी हैं कि वे बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी। विपक्ष के कई दूसरे नेता भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान मोहब्बत की दुकान, संविधान की रक्षा और संविधान की कॉपियां लेकर देशभर में घूमते थे। और भाजपा पर संविधान विरोधी होने और संविधान बदलने का आरोप लगाते थे। यही इनका मूल चरित्र है।

2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने भाजपा के सत्ता में आने के बाद ह्यसंविधान बदलने का खतरा' होने का मुद्दा उठाया था। इससे कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी। उसी तरह विपक्ष लोगों के बीच वोट खोने का डर और चुनाव में गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर बढ़त हासिल करना चाहता है। इससे वह सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने के साथ-साथ जनता के बीच अपनी पकड़ भी मजबूत करना चाहता है। यदि जनता के एक प्रतिशत लोगों के मन में भी अपना 'वोट खोने का डर' पैदा हो जाता है तो इससे पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। कांग्रेस-राष्ट्रीय जनता दल पूरी तैयारी के साथ इसी 'रणनीति' पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

चुनाव आयोग ने केवल दूसरी जगह चले गए मतदाताओं, मृतकों और एक ही व्यक्ति के दो स्थानों पर मतदाता सूची में शामिल होने वाले मतदाताओं का नाम ही मतदाता सूची से हटाने की बात कही है, ऐसे में एसआईआर का विरोध पूरी तरह से अतार्किक है। चुनाव आयोग नियम कानून के तहत वोटर लिस्ट अपडेट कर रहा है। यह उसकी डयूटी का हिस्सा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वच्छ और स्पष्ट मतदाता सूची जरूरी है। वास्तव में, मतदाता सूची पर विपक्ष का हंगामा केवल राजनीतिक स्टंट कर जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश है। विपक्ष चुनावों में अपनी हार को देखकर अभी से बहाने की तलाश कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन और चुनाव आयोग पर बयानबाजी उसी का नतीजा है।

केशव मौर्य के सहारे ओबीसी दांव

अजय कुमार

भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा मंथन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में पार्टी को मिले अपेक्षाकृत कमजोर जनादेश के बाद संगठन के पुनर्गठन की जरूरत महसूस की जा रही है। राज्य में अब तक भूपेंद्र चौधरी के बाद किसी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो सकी है, और इस विलंब को लेकर भाजपा कार्यकताओं में सवाल भी उठने लगे हैं। इस बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की बढ़ती सक्रियता, दिल्ली में लगातार शीर्ष नेताओं से मुलाकातें और ओबीसी समीकरण को लेकर उनका नाम चर्चा के केंद्र में आ गया है।उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में चिंताजनक रहा। जहां 2019 में भाजपा ने सहयोगियों सहित 64 सीटें जीती थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 36 रह गई। इसमें भी भाजपा अकेले 33 सीटें जीत पाई, जबकि सपा-कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटों पर कब्जा जमाकर स्पष्ट संकेत दे दिया कि विपक्ष की सामाजिक रणनीति ने भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाई है। खासतौर पर ओबीसी और दलित समुदाय के मतदाताओं का झुकाव सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फामूर्ले की ओर गया।

ऐसे में भाजपा के रणनीतिकारों को यह समझ में आ गया है कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत की हैट्रिक बनानी है, तो संगठन को फिर से सशक्त करना होगा। यही वजह है कि पार्टी अब ऐसा चेहरा तलाश रही है, जो न सिर्फ संगठनात्मक अनुभव रखता हो, बल्कि सामाजिक समीकरणों को साधने में भी सक्षम हो। इस समीकरण में सबसे उपयुक्त नाम एक बार फिर उभर कर आया है केशव प्रसाद मौर्य का।8 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकातों ने चचाओं को हवा दी। यह मुलाकातें केवल शिष्टाचार नहीं मानी जा रही हैं, बल्कि इन्हें संगठन के पुनर्गठन और आगामी चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खुद केशव मौर्य ने इस बात की पुष्टि की है कि इन बैठकों में 2027 की जीत की रणनीति पर चर्चा हुई। यह वही केशव मौर्य हैं, जिनके नेतृत्व में 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 403 में से 312 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। उस समय वे प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया था।

मौर्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे भाजपा के मूल कार्यकर्ता रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से होते हुए पार्टी की मुख्यधारा में आए। उनका व्यक्तित्व एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर उपमुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले नेता का है, जो पार्टी के जमीनी कार्यकताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि संगठन को फिर से सक्रिय और ऊजार्वान बनाने के लिए उनके नाम पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।केशव मौर्य का नाम भाजपा के लिए इस समय और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि पार्टी को एक बार फिर ओबीसी समुदाय को अपने साथ मजबूती से जोड़ना है। भाजपा को अच्छी तरह से यह एहसास हो चुका है कि विपक्ष, खासकर सपा, ओबीसी वोट बैंक को खींचने

की पूरी कोशिश में है। अखिलेश यादव ने पीडीए फामूर्ले को जिस तरीके से पेश किया है, उसमें ओबीसी और दलित वर्ग को प्रमुखता दी गई है। ऐसे में भाजपा को जवाब उसी अंदाज में देना होगा। और यह काम केशव मौर्य जैसे कद्दावर ओबीसी नेता ही कर सकते हैं, जिनकी सामाजिक स्वीकार्यता व्यापक है।

हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष पद पर फैसला केवल सामाजिक समीकरणों के आधार पर नहीं लिया जाएगा। इसके पीछे संगठन और सत्ता के बीच संतुलन की भी बड़ी भूमिका है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ को 2027 में मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में दोबारा प्रोजेक्ट किया जाना तय है। लेकिन समय-समय पर पार्टी के अंदर से ऐसी आवाजें उठती रही हैं कि केशव मौर्य को भी सीएम पद का दावेदार घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे में पार्टी के लिए यह जरूरी हो जाता है कि मौर्य को संगठन में लाकर उन्हें सत्ता की दौड़ से बाहर रखा जाए, ताकि योगी आदित्यनाथ का रास्ता साफ रहे।इस पूरी रणनीति के पीछे केंद्रीय नेतृत्व की सोच यह है कि पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए, जो न सिर्फ सामाजिक समीकरणों को साधे बल्कि संगठन को भी धार दे। और इस पैमाने पर केशव मौर्य खरे उतरते हैं। यही कारण है कि अमित शाह ने हाल ही में एक कार्यक्रम में मौर्य को ह्यप्रिय मित्रह्व कहकर संबोधित किया, जबकि योगी आदित्यनाथ को ह्यलोकप्रिय मुख्यमंत्रीह्व बताया। यह संकेत है कि पार्टी नेतृत्व दोनों नेताओं को संतुलित रूप से आगे बढ़ाना चाहता है।

इस बीच भाजपा के भीतर और भी कई नामों पर विचार किया जा रहा है। ओबीसी वर्ग से स्वतंत्रदेव सिंह, अमर पाल मौर्य, धर्मपाल सिंह लोधी, बीएल मौर्य और बाबूराम निषाद के नाम चर्चा में हैं। वहीं दलित समुदाय से बेबी रानी मौर्य का नाम भी सामने आया है। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के नामों पर विचार हो रहा है। यदि पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना चाहती है, तो जितिन प्रसाद और महेश शर्मा जैसे नेता विकल्प हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर देरी के पीछे चार प्रमुख कारण माने जा रहे हैं पहला, नया अध्यक्ष किस जाति या वर्ग से

होगा; दूसरा, क्या वह पूर्वांचल से होगा या पश्चिम यूपी से; तीसरा, क्या वह विपक्ष के पीडीए समीकरण को तोड़ पाएगा; और चौथा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस नाम से सहज होंगे। सूत्रों की मानें तो पार्टी इन चारों सवालों पर गहन मंथन कर रही है और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।अभी तक पार्टी की रणनीति यही रही है कि 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को पहले से तैयार किया जाए। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पार्टी जल्दबाजी नहीं दिखा रही है। लेकिन यह भी सच है कि संगठनात्मक स्तर पर खालीपन लंबे समय तक नहीं चल सकता। कार्यकताओं को दिशा देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है। और यही वजह है कि अब पार्टी पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह जल्द से जल्द इस नियुक्ति को अंतिम रूप दे।

अगर केशव मौर्य को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, तो भाजपा एक साथ कई निशाने साध सकेगी एक, संगठन को अनुभव और जनाधार से लैस नेतृत्व मिलेगा; दो, ओबीसी समाज को संदेश जाएगा कि पार्टी उनके भरोसे पर कायम है; और तीन, सत्ता और संगठन के बीच संतुलन बना रहेगा, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को चुनौती नहीं मिलेगी।अब सबकी निगाहें दिल्ली पर हैं, जहां से भाजपा के बड़े फैसले होते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा एक बार फिर केशव मौर्य पर भरोसा जताएगी या किसी नए चेहरे को सामने लाकर चौंकाएगी। लेकिन इतना तय है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भाजपा की 2027 की रणनीति का पहला बड़ा संकेत होगी। और संभव है कि यह संकेत संगठन में नई ऊर्जा और विपक्ष को सीधी चुनौती देने की दिशा में पहला कदम हो।

बिहार में पूर्वी भारत के विकास की अंगड़ाई

राष्ट्र समाज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी, बिहार के गांधी मैदान में एक चुनाव पूर्व रैली कर 7217 करोड़ रुपये की विभिन्न लोक लुभावन परियोजनाओं की सौगात दी। देखा जाए तो आगामी अक्टूबर-नवम्बर माह में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बीते महज 45 दिनों यानी डेढ़ महीने में उनका यह तीसरा बिहार दौरा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उन्होंने 20 जून को सीवान में और 30 मई को बिक्रमगंज (रोहतास) में उनकी रैली हुई थी, जिस दौरान भी उन्होंने उन इलाकों में हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरूआत हुई थी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके दौरे और बढ़ेंगे, जिससे साफ है कि यूपी में लगातार दूसरी पारी खेल रही भाजपा की देशव्यापी सफलता के लिए बिहार विस चुनाव अब काफी अहम हो चुका है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब बिहार में पूर्वी भारत के विकास की अंगड़ाई आकार लेगी तो पड़ोसी राज्यों में भाजपा की सरकारें खुद-ब-खुद बनती चली जाएंगी। बस, थोड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे वो कतई नहीं हिचकते। दरअसल, इसकी दो वजहें हैं- पहली, सियासत में यूपी-बिहार को महाराष्ट्र-गुजरात, राजस्थान-मध्यप्रदेश, हरियाणा-पंजाब, पश्चिम बंगाल-असम, कर्नाटक-आंध्रप्रदेश और केरल-तमिलनाडु आदि की तरह ही जुड़वा भाई समझा जाता है। दूसरी, भाजपा की सबसे पुरानी गठबंधन सहयोगी पार्टी जदयू अपनी प्रतिस्पर्धी राजनीतिक पार्टी राजद से जमीनी सियासी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे ब्रेक के बाद भाजपा के सुनहरे राजनीतिक सपने भी प्रभावित होते आए हैं।

यही वजह है कि यहां पर एनडीए के साथ-साथ भाजपा का भी मजबूत होना बेहद जरूरी है।

चूंकि हाल के वर्षों में पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की फतह, फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत, ततपश्चात दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की फतह और उसके बाद उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के मुख्य सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं, इसलिए उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत एनडीए की फतह के लिए अपना होमवर्क शुरू ही नहीं किया, बल्कि उसे तेज कर दिया है। यह इसलिए भी जरूरी है कि अगले वर्ष पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे जीतना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए कि यह जनसंघ (अब भाजपा) के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह प्रदेश के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता को प्रभावित करने वाला प्रदेश भी है। अभी हाल ही में बंगलादेश (पूर्वी पाकिस्तान) से जो चुनौती मिली या मिल रही है, उससे पश्चिम बंगाल में भाजपा का मजबूत होना अब राष्ट्रीय जरूरत बन चुकी है।

वहीं, वर्ष 2026 में ही असम विधानसभा के चुनाव भी होंगे, जिसमें भाजपा के कद्दावर मुख्यमंत्री हिमंता विश्वशर्मा की सरकार को रिपीट करवाना भी भाजपा नेतृत्व के लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि पूर्वोत्तर में भाजपा और एनडीए की बढ़त के पीछे असम की सियासत का बड़ा योगदान है। अपने देखा होगा कि तमाम तैयारियों के बावजूद भाजपा विगत झारखंड विधानसभा चुनाव में एक छोटी क्षेत्रीय पार्टी झामुमो के हाथों शिकस्त खा चुकी थी, क्योंकि उसे इंडिया गठबंधन का मजबूत साथ मिल गया। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी भारत के सभी राज्यों में भाजपा को मजबूत करने की कमान अपने हाथ में ले ली है। क्योंकि ह्यमोदी है तो जीत मुमकिन है' वाला सियासी फॉर्मूला प्रायः हर जगह पर हिट हो जाता है। बता दें कि देश के पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर-पूर्व के सात बहन राज्यों की भी गणना की जाती है, जिसमें असम का राजनीतिक स्थान महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि पूर्वी भारत के 11 राज्य देश के सर्वाधिक पिछड़े और गरीब राज्यों में से एक हैं, जहां के लोगों का जीवन स्तर भी

अपेक्षाकृत निम्न है। इसलिए भाजपा की सकारात्मक पहल यहां रंग ला सकती है।

यही वजह है कि बिहार की सियासी यात्राओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी भारत के विकास के सुनहरे सपने दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने मोतिहारी में दो टूक कहा- हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी को बनाना है। पूर्वी भारत के विकास के लिए बिहार को विकसित बनाना है। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि आज बिहार में तेजी से विकास का काम हो रहा है, क्योंकि केंद्र और बिहार में एनडीए की डबल इंजन सरकार है।

पीएम मोदी ने आगे कहा कि जैसे अवसर गुरुग्राम में हैं, वैसे ही अवसर गया जी में भी बनें। पुणे की तरह पटना में भी औधोगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बंगलुरू की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़ें। ये इसलिए संभव है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। देखा जाए तो पूर्वी भारत के किसी भी राज्य में पीएम मोदी जाएं, लगभग एक समान बातें दोहराते हैं, ताकि पूर्वी भारत भी उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत की तरह ही समग्र विकास के पैमाने पर खरा उतर सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी से एनडीए के चुनाव अभियान को एक कदम और आगे बढ़ाया है। यहां पर लाखों लोगों की मौजूदगी में उन्होंने ह्फिर एक बार एनडीए सरकारह्व का नारा बुलंद किया। वहीं, भाषण सुनने पहुंची महिलाओं से मुखातिब होते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका है। यह भी याद दिलाया कि नीतीश कुमार ने जीविका के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया। केंद्र सरकार भी अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए संकल्पित है।

नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी ताकत बिहार के माता बहनों की है। एनडीए द्वारा उठाए जा रहे एक-एक कदम का महत्व बिहार की माताएं बहने अच्छी तरह समझती हैं। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। यह बिहार की बढ़ती ताकत में उनकी भागीदारी का संकेत है। पहले ना बैंकों में उनका ना खाता होता था, ना कोई घुसने देता था। आपको 10 रुपए भी छुपा कर रखना पड़ता था। इसलिए मोदी ने गरीब के लिए बैंकों के दरवाजे खुलवा दिए और अभियान चलाकर जनधन खाते खुलवाए। इसका सबसे बड़ा लाभ दलित परिवार की महिलाओं को मिला और आज 3.5 करोड़ जनधन खाते हैं। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा इन खातों में जा रहा है।

दूसरी ओर इंडी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव कांग्रेस और वामपंथी दलों को साधते हुए रोजगार,

शिक्षा, भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यही वजह है कि कुछ सर्वे में उन्हें भी अच्छा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, खासकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं में। हालांकि, आप के इंडिया गठबंधन से अलग होने और बिहार में उसके अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा से राजद-कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी है। वहीं, एआईएमआईएम से राजद-कांग्रेस की यदि चुनावी पटरी नहीं बैठी तो वह भी चुनावी ताल ठोकेगी, जिससे धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा तय है। भाजपा यही चाहती भी है। जबकि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि उन्हें सीमित सीटों पर समर्थन मिल सकता है, फिलहाल राज्यभर में कोई व्यापक लहर उनके पक्ष में नजर नहीं आ रही है। हालांकि, श्री किशोर मशहूर सियासी रणनीतिकार रहे हैं, जो चुनाव के अंतिम क्षणों में हवा का रुख मोड़ने में माहिर समझे जाते हैं। चूंकि भाजपा, कांग्रेस, जदयू, टीएमसी, आप के अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियों के वे और उनके लोग सलाहकार रहे हैं, इसलिए अपने विशालकाय सियासी रणनीतिक अनुभवों से वो बिहार में मजबूती पूर्वक अपनी जड़ें जमा चुके हैं। यदि बिहार के सवर्णों ने एकजूट होकर प्रशांत किशोर के जनसुराज को वोट दे दिया तो एनडीए और इंडी गठबंधन के कांटे की टक्कर में वो 75-100 से ज्यादा सीटें निकाल सकते हैं।

ऐसा इसलिए कि बिहार के सवर्ण विगत 35 सालों से यादव-लवकुश समीकरण के बीच सत्ता की अदला-बदली और बेलगाम अपराध-भ्रष्टाचार से ऊब चुके हैं, इसलिए प्रशांत किशोर में उन्हें अपना भविष्य नजर आ रहा है। हालांकि, प्रशांत किशोर भी अत्यंत पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को अपनी पार्टी से जोड़ रहे हैं। ऐसे में यदि सवर्णों का सियासी जोरन उन्हें मिल गया तो उनकी सत्ता तक पहुंचने वाली जनतांत्रिक दही जम सकती है। इससे उनके समर्थकों का सेहतमंद होना स्वाभाविक है।

पीएम मोदी मोतिहारी सभा में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ रुपये भी जारी किए। इसके अलावा, 12 हजार लाभार्थियों के गृह प्रवेश के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 40 हजार लाभार्थियों को 160 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए।

पीएम ने बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी की जिक्र किया। कहा कि कुछ दिन पहले नीतीश जी की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़कर 1100 कर दी। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ही जाएगा। पिछले डेढ़ महीने में ही बिहार के 24000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह को 1000 करोड रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। नारी सशक्तिकरण के प्रयासों से परिणाम भी दिखने लगे हैं। बिहार में लखपति दीदी की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3 करोड़ बहनों को देशभर में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डेढ़ करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी हैं। चंपारण में भी यह संख्या 80000 से ज्यादा है। आज यहां 400 करोड रुपए का सामुदायिक निवेश फंड भी शुरू किया गया है। यह पैसा नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में काम आएगा। नीतीश जी ने जो जीविका दीदी योजना चलाई है वह बिहार के लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता है। पीएम ने कहा कि भाजपा एनडीए का विजन है कि जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है कि समृद्ध बिहार हर युवा को रोजगार। बिहार के नौजवानों को बिहार में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले इसलिए तेजी से काम किया जा रहा है। नीतीश सरकार में लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार नौकरी दी है। नीतीश जी ने बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए अवसर दिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी।

BIKANERVALA

Traditional Indian Sweets

SINCE 1905

At all BIKANERVALA you can always be sure of quality and taste that is what makes our huge range of Sweets, Snacks & Traditional Indian Food the most reliable and dependable products.

BIKANO

BIKANO is our range of Packaged Namkeens, Sweets, Sherbets, Papad and Pickles with a dependable shelf life. These are popular not only in India but also in the quality conscious overseas markets like Europe, America, Canada, Middle East and many more

VISIT BIKANERVALA OUTLETS IN : INDIA | USA | CANADA | U.A.E. | QATAR | BAHRAIN | UK | NEW ZEALAND | SINGAPORE | NEPAL

www.bikanervala.com

पंजाब में तेजी से बिगड़ रही कानून

डॉ. आशीष वशिष्ठ

पंजाब में तेजी से बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन और बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और उस पर सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों पर इस हफ्ते पंजाबी अखबारों ने अपनी राय प्रमुखता से रखी है। सूबे की कानून व्यवस्था पर चंडीगढ़ से प्रकाशित पंजाबी ट्रिब्यून अपने संपादकीय 'पंजाब में बढ़ता अपराध' में लिखता है- अबोहर के व्यापारी संजय वर्मा की दिनदहाड़े हत्या और मोगा के एक क्लीनिक में अभिनेत्री तानिया के पिता की गोली मारकर हत्या ने एक तरह से यह उजागर कर दिया है कि किस तरह संगठित अपराध राज्य में आपराधिक गतिविधियों को आसानी से अंजाम दे रहा है। अखबार लिखता है शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी, नशे की लत व जल्दी पैसे कमाने का लालच कई पंजाबी युवाओं को अपराध की ओर धकेल रहा है। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार और गैंगस्टरों का महिमामंडन आग में घी डालने का काम कर रहा है। पंजाब में आपराधिक-आतंकवादी गठजोड़ अब स्थानीय नहीं रहा; यह अंतर्राष्ट्रीय, तकनीकी रूप से सक्षम और वैचारिक रूप से अस्थिर हो गया है। यह संकट जितना लंबा चलेगा, पंजाब के भविष्य को पटरी पर लाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा।

जालंधर से प्रकाशित 'पंजाबी जागरण' लिखता है- पंजाब पिछले कुछ समय से आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण सुर्खियों में है। अबोहर में हुई एक घटना ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े एक समूह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस घटना की जिम्मेदारी ली है। ऐसा नहीं है कि राज्य में इस तरह की यह पहली घटना है। यह घटना आम बात है। अबोहर की घटना ने पंजाब में जबरन वसूली के बढ़ते मामलों पर भी प्रकाश डाला है।

जालंधर से प्रकाशित अजीत लिखता है– आजकल पूरे राज्य में लूटपाट का बोलबाला है। अबोहर की घटना के बाद सरकार एक बार फिर विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। विपक्ष खासकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विशेष बहस की मांग की है।

जालंधर से प्रकाशित रोजाना पंजाब टाइम्स लिखता है–वर्ष 2023-24 की रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब में जबरन वसूली और धमकियों से जुड़े मामलों में वृद्धि देखी गई है। पंजाब पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, जून 2022 से फरवरी 2023 तक जबरन वसूली और धमकी के 278 मामले दर्ज किए गए, जो मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक बढ़कर 307 हो गए। यह वृद्धि समाज और पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। अखबार लिखता है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने संगठित अपराध की गंभीरता को उजागर किया, इसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जबरन वसूली की घटनाओं ने पंजाब के व्यापारियों और छोटे उद्योगपतियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। कई व्यापारी-कलाकार धमकियों के कारण अपना व्यवसाय या पेशा छोड़ने की सोच रहे हैं। इसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

चंडीगढ़ से प्रकाशित रोजाना स्पोक्समैन लिखता है, इस साल अब तक चंडीगढ़ में हत्या के 15 मामले दर्ज किए गए हैं। आंकड़े

-व्यवस्था

बताते हैं कि तेजी से हो रहे शहरीकरण, अन्य कारकों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार से पंजाब और चंडीगढ़ की ओर युवा पीढ़ी के बढ़ते पलायन के कारण भी गंभीर और घातक अपराधों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जिन व्यवसायों में स्थानीय लोगों की विशेषज्ञता है, उनमें बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांगें राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उठने लगी हैं। पंजाब और चंडीगढ़ को भी अब इस दिशा में कुछ सार्थक कदम उठाने की जरूरत है।

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट के हालिया निदेर्शों पर चंडीगढ़ से प्रकाशित 'पंजाबी ट्रिब्यून' लिखता है- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही उसने चुनाव आयोग से एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछा हैः अभी क्यों? अदालत ने यह बिल्कुल सही बात कही है कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह की कवायद से लोगों के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि इस प्रक्रिया में आधार कार्ड पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। उसका मानना है कि चुनाव अधिकारियों को आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर विचार करना चाहिए। चंडीगढ़ से प्रकाशित 'देशसेवक' लिखता है- छोटी-मोटी बाधाओं के बावजूद, चुनाव आयोग ने न केवल देश में, बल्कि दुनिया में भी सम्मान अर्जित किया है। बिहार चुनावों में चुनाव आयोग के सामने अपनी ईमानदारी बचाने की चुनौती है।

जालंधर से प्रकाशित 'अज दी आवाज' लिखता है– बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। रसूखदारों और कारोबारियों की हत्याओं की घटनाओं ने राज्य सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है। युवा बेरोजगार हैं और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार ने भी अन्य राजनेताओं की तरह चुनाव के दौरान जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े ऐलान किए हैं। अखबार आगे लिखता है, बिहार सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत के लिए चुना गया समय उसकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहा है। अगर सरकार वाकई लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर और सजग होती, तो ये घोषणाएं एक-दो साल पहले ही की जा सकती थीं। यह तो समय ही बताएगा कि सरकार के अंतिम दिनों में मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई घोषणाएं कारगर साबित होती हैं या नहीं।

महाराष्ट्र में उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन पर जालंधर से प्रकाशित 'अज दी आवाज' लिखता है- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने के फैसले ने दोनों चचेरे भाइयों, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को करीब आने का अवसर दिया। ऐसा लगता है मानो दोनों नेता साथ आने के मौके का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल, ये दोनों पार्टियां अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हैं। ठाकरे भाइयों का तात्कालिक लक्ष्य प्रतिष्ठित मुंबई नगर निगम में पैर जमाना है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति और विपक्षी एमवीए दोनों ही आंतरिक मतभेदों से घिरे हुए हैं। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर, आगामी समय में महाराष्ट्र की राजनीति में और अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे और उनका प्रदर्शन राजनीति में उनका भविष्य भी तय करेगा। इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये दोनों स्थानीय चुनाव अकेले लड़ेंगे या एमवीए के सहयोगी कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे। चंडीगढ़ से प्रकाशित 'पंजाबी ट्रिब्यून' लिखता है– शिवसेना के एक धड़े के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा हताशा में अपनाया गया यह अंतिम उपाय है। शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के बेटे उद्धव और भतीजे राज ठाकरे अपनी राजनीतिक किस्मत चमकाने के लिए 'मराठी मानुष' कार्ड पर भरोसा कर रहे हैं। वे भाजपा पर किसी न किसी बहाने महाराष्ट्र के लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं; हालांकि, उनकी लड़ाई केवल भगवा पार्टी के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली 'आधिकारिक' शिवसेना के खिलाफ भी है। ठाकरे बंधुओं के पुनर्मिलन का मतलब है कि शिंदे अब मराठी वोट को हल्के में नहीं ले सकते।

ठाकरे भाइयों ने समाज को भाषा के नाम पर बांट दिया

प्रमोद तिवारी

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर भाषा की भावनाओं की लहरों में डोलती दिखाई दे रही है। मराठी अस्मिता के सवाल को फिर से केंद्र में लाते हुए शिवसेना (उद्धव गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने हिंदी भाषा को कथित रूप से 'थोपे जाने' के विरोध में एक समान सुर अपनाया है। यह घटनाक्रम न केवल राज्य की भाषाई राजनीति को गर्मा गया है, बल्कि वर्षों से एक-दूसरे के विरोध में खड़े ठाकरे बंधुओं को साझा राजनीतिक उद्देश्य के तहत साथ भी ले आया है।

से राज ठाकरे और उनकी पार्टी की ओर से हिंदी भाषा का विरोध पहले भी होता रहा है। खासकर मुंबई जैसे महानगर में जहाँ हिंदी भाषी आबादी बड़ी संख्या में है, वहां मराठी भाषी समाज के मन में यह भाव डाला जा रहा है कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और भाषा को धीरे-धीरे हाशिये पर डाला जा रहा है। राज ठाकरे की मनसे ने पहले भी हिंदी भाषियों पर निशाना साधते हुए ऑटो रिक्शा चालकों और बहुभाषी दुकानों के खिलाफ अभियान चलाए हैं। वहीं शिवसेना की स्थापना ही 'मराठी मानुष' की राजनीति पर हुई थी, हालांकि बाद के वर्षों में वह राष्ट्रीय राजनीति और गठबंधनों में आगे बढ़ती चली गई। दोनों भाई दो दशक के बाद एक ही मंच से

जिस तरह गरजे हैं उससे हिंदी भाषियों के मन में सुरक्षा को लेकर आशंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है इसलिए महाराष्ट्र सरकार को अब और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है।

आज दोनों चचेरे भाइयों उद्धव और राज ने साथ आकर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई शुरूआत भी कर दी है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक राजनीतिक परिवारों को बंटते देखा गया लेकिन ठाकरे बंधुओं ने एक साथ आकर जो पहल की है क्या उसका विस्तार पवार परिवार तक भी होता है, अब इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। रैली में उद्धव और राज ठाकरे ने अपने भाषण के जरिये वैसे तो कई बड़ी बातें कहीं लेकिन उन्हें हिम्मत करके कुछ जायज सवालों के जवाब भी देने चाहिए।

1. पहला सवाल यह है कि जिस हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा हासिल है उसके खिलाफ नफरत क्यों फैलाई जा रही है?

2. दूसरा सवाल यह है कि हिंदी सिनेमा उद्योग ने जिस मुम्बई को विशिष्ट पहचान दिलाई और जो हिंदी सिनेमा उद्योग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की तरह है वहां हिंदी का विरोध करना क्या दोहरा रवैया नहीं है? फिल्मों को हिंदी बेल्ट से कमाई चाहिए लेकिन उसी हिंदी बेल्ट का व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में हिंदी बोले तो क्या उसकी बेल्ट से पिटाई की जायेगी?

3. तीसरा सवाल यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर तमाम अन्य मराठा वीरों ने तो अपने साम्राज्य का उत्तर और दक्षिण तक विस्तार किया था लेकिन उद्धव और राज मराठियों को संकुचित दायरे में ही क्यों रखना चाहते हैं?

हिंदी विरोध के बहाने साथ आये उद्धव और राज को समझना चाहिए कि हिंदी वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह भारत की सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन चुकी है। विदेशों में भी भारतीय, हिंदी को अपने मूल से जोड़ने वाली डोर मानते हैं। हिंदी पर मराठी भाषा की जीत का उत्सव मना रहे उद्धव और राज को समझना चाहिए कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान का अभिन्न अंग है।

जन समर्थन खो चुके उद्धव और राज ठाकरे जैसे हिंदी विरोधियों को अपने मन की वह भ्रांति दूर कर लेनी चाहिए कि हिंदी कोई विरोधी भाषा है, उन्हें समझना चाहिए कि हिंदी तो एक सहयोगी भाषा है। यह कभी किसी पर थोपी नहीं जाती बल्कि अपनी उपयोगिता, पहुँच और आत्मीयता के बल पर यह जनमानस में रची-बसी है। हिंदी तो वह भाषा है जो भारत की भाषायी विविधता को बनाए रखते हुए अन्य भाषाओं के साथ बड़ी आसानी से समन्वय कर लेती है। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए साथ आये उद्धव और राज ठाकरे को समझना चाहिए कि हिंदी एक लचीली और समावेशी भाषा है जो अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करती है। इसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगाली, क्षेत्रीय बोलियों और यहां तक कि अंग्रेजी के शब्दों को भी आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है।

देश और समाज को जोड़ने वाले मुद्दों को उठा कर अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की बजाय समाज को बांटने वाले मुद्दे उठा कर उद्धव और राज ठाकरे को समझना चाहिए कि हिंदी किसी को दबाने या हटाने की भाषा नहीं है, बल्कि यह जोड़ने की भाषा है। यह 'विविधता में एकता' के भारतीय दर्शन को व्यवहार में उतारती है। उद्धव और राज ठाकरे को समझना चाहिए कि हिंदी भारत की आत्मा की आवाज है, यह उस किसान की बोली है, उस सैनिक का आदेश है, उस कवि की कल्पना है और उस आम आदमी का माध्यम है जो पूरे देश से जुड़ना चाहता है। इसे समझना, अपनाना और सम्मान देना ही असली भारतीयता है। आज जो लोग उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने पर नृत्य कर रहे हैं उन्हें भी यह बात समझनी चाहिए कि चचेरे भाई तो आपस में जुड़ गये मगर आपको भाषा के नाम पर भड़का कर अपने पड़ोसियों और अपने सहयोगियों से अलग कर दिया।

बहरहाल, जहां तक उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की बात है तो आपको बता दें कि दोनों नेताओं का एक साथ आना महज भाषाई चिंता नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग होने और एकनाथ शिंदे की ओर से शिवसेना को विभाजित कर देने के बाद नए सिरे से अपनी 'असली शिवसेना' की छवि को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राज ठाकरे को भी लंबे समय से राजनीतिक पुनर्जीवन की तलाश है और मराठी अस्मिता का मुद्दा उनके लिए सबसे सहज विकल्प है। देखा जाये तो दोनों के लिए 'हिंदी विरोध' एक ऐसा मंच है, जहां वे एक बार फिर मराठी मतदाता के भावनात्मक जुड़ाव को सक्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनावों को ध्यान में रखते हुए।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौता: एक क्रांतिकारी कदम

ललित गर्ग

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की अंतिम स्वीकृति ने न केवल वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य को भी एक नई दिशा दी है। दोनों देशों के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का फायदा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से संरक्षणवाद बढ़ा है, उसमें ऐसे व्यापार समझौतों की भूमिका और भी अहम हो जाती है। इस समझौते से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल अमेरिका बल्कि अन्य देशों को भी भारत की मजबूत होती स्थिति का आइना दिखाया है, जो उनकी दूरगामी एवं कूटनीतिज्ञ राजनीति का द्योतक है। इस समझौते को मौजूदा दौर में दुनियाभर में जारी बहुस्तरीय तनाव, दबाव एवं दादागिरी की राजनीति के बीच एक बेहतर एवं सूझबूझभरी कूटनीतिक कामयाबी के तौर पर देखा जा सकता है। यह छिपा नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने शुल्क के मोर्चे पर एक बड़ा द्वंद्व एवं संकट खड़ा कर दिया था। लेकिन भारत ने इस द्वंद्व के बीच झुकने की बजाय नये रास्ते खोजे हैं। निश्चित ही यह व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) महज एक कागजी करार नहीं, बल्कि ह्यविकसित भारत 2047ह्ल के स्वप्न को मूर्त रूप देने की ठोस रणनीति है। जहां एक ओर यह समझौता 99 प्रतिशत टैरिफ को समाप्त कर वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, कृषि व रत्न-आभूषण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को नई उड़ान देगा, वहीं दूसरी ओर छोटे उद्यमों, मछुआरों और किसानों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाएगा। भारत के ग्रामीण अंचलों से हल्दी, दाल, अचार जैसे उत्पाद अब ब्रिटिश बाजारों में अपनी महक फैलाएंगे।

मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में जिस प्रकार से गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता पर जोर दिया, उसी का परिणाम है यह करार। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि अब भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए विश्व से संवाद करता है। यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह सेवा क्षेत्र, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, निवेश, सामाजिक सुरक्षा, और दोहरे कराधान जैसे क्षेत्रों में भी भारतीयों के लिए नए दरवाजे खोलता है। खासकर ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए यह राहत का संदेश है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिल सकेगी। यह समझौता इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि अब तक अमेरिका की ओर से पैदा किये गये किसी दबाव के आगे भारत ने झुकना स्वीकार नहीं किया और उसने भारत-

ब्रिटेन जैसे नये विकल्पों को खड़ा करने और पुराने को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाये हैं।

ब्रिटेन के साथ यह एफटीए एक उदाहरण है कि कैसे भारत न्यायसंगत और समावेशी व्यापार समझौते कर सकता है, जिसमें न तो अपने किसानों, न ही डेयरी क्षेत्र या छोटे उत्पादकों को नुकसान होता है। भारत ने संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखकर आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा की अपनी नीति को बरकरार रखा है। वर्तमान में भारत का वैश्विक व्यापार लगभग 21 अरब डॉलर है, जो इस समझौते के बाद 2030 तक 120 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना रखता है। यह न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग हिस्सेदारी को 17 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने में सहायक होगा। इस करार के साथ, मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि जब नियोजित दृष्टिकोण, वैश्विक प्रतिष्ठा और साहसिक निर्णय साथ चलते हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश भी वैश्विक मंच पर निर्णायक बन सकते हैं।

भारत और ब्रिटेन के बीच सीईटीए के अस्तित्व में आने से एक नये आर्थिक सूर्य का उदय हुआ है, जिससे रोजगार सहित अनेक उन्नत राष्ट्र-निर्माण के अवसर सृजित होंगे। सीईटीए की संकल्पना आस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और कुछ अन्य देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के अनुरूप ही है। यह मोदी सरकार की भारत को 2047 तक विकसित बनाने की संकल्पना से जुड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। मोदी सरकार ने भारत को तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनाने के अपने संकल्प में नये पंखों को जोड़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास को फिर से स्थापित करने तथा इसे भारतीय और विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक दृढ़ रणनीति अपनाई है। विकसित देशों के साथ एफटीए इस रणनीति के केंद्र में है। ऐसे समझौते व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चितताओं को दूर करके निवेशकों का विश्वास बढ़ाते हैं। पिछली यूपीए सरकार ने भारत के व्यापारिक दरवाजे प्रतिद्वंद्वी देशों के

लिए खोलकर भारतीय व्यवसायों को खतरे में डालने वाला रवैया अपनाया था, अतीत की उन बड़ी भूलों को सुधारा जा रहा है, जो नये भारत-विकसित भारत का आधार है।

क्रांतिकारी सुधारों, नवाचार, तकनीक, कारोबारी सुगमता और प्रधानमंत्री के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आर्थिक सूरज के रूप में उभारने में मदद की है, जहां विपुल संभावनाएं हैं। आज दुनिया भारत की ओर आशाभरी नजरों से देख रही है और भारत की अद्भुत विकासगाथा का हिस्सा बनना चाहती है। प्रमुख देशों द्वारा एक के बाद एक एफटीए इसी मान्यता की पुष्टि करते हैं। ब्रिटेन के साथ यह व्यापार समझौता बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के एफटीए वस्तुओं और सेवाओं से कहीं आगे तक सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं नागरिक हितों तक जाते हैं। आस्ट्रेलियाई एफटीए के साथ भारत ने दोहरे कराधान का मुद्दा सुलझाया, जो आईटी कंपनियों की परेशानी बढ़ा रहा था। ब्रिटेन के साथ समझौते का एक अहम बिंदु दोहरे अंशदान से जुड़ा है। यह ब्रिटेन में नियोक्ताओं, अस्थायी भारतीय कर्मियों को तीन वर्षों के लिए सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट देता है। इससे भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को अब अनेक सुविधाएं मिलेगी।

साल 2014 के बाद से भारत ने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए के साथ फ्री व्यापारिक समझौते किये हैं। ईएफटीए का अर्थ है यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। यह एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसमें चार यूरोपीय देश शामिल हैं- आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। यूरोप से बातचीत जारी है, जिसे जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। अर्थ-व्यवस्था के मोर्चे पर आने वाली चुनौतियों से निपटने में ऐसे समझौते सहायक होंगे।

इस बीच, अगर भारत की अमेरिका के साथ अच्छी व्यापार डील होती है तो उससे भी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की ओर कदम बढ़ेंगे। लेकिन ब्रिटेन से समझौता केवल व्यापार नहीं, भविष्य का निर्माण है। यह कृषि को समृद्धि, उद्योग को विस्तार, युवाओं को अवसर, और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर सशक्त करता है। निश्चित ही जहां बाजार बनते हैं अवसरों के, वहीं नीति बनती है भविष्य की नींव। भारत और ब्रिटेन के इस करार से विश्व सुनेगा अब भारत की गूंज!

वायु प्रदूषण से स्मृति-लोप का बढ़ता खतरा

राष्ट्र समाज

पर्यावरण की उपेक्षा एवं बढ़ता वायु प्रदूषण मनुष्य स्वास्थ्य के लिये न केवल घातक हो रहा है, बल्कि एक बीमार समाज के निर्माण का कारण भी बन रहा है। हाल ही में हुए एक मेटा-अध्ययन ने वायु प्रदूषण और बिगड़ती स्मृति के बीच एक खतरनाक संबंध का खुलासा किया है। हवा में मौजूद विषैले कण-खासकर महीन धूल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें, जो मुख्य रूप से वाहनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलती हैं, हमारे मस्तिष्क को सीधे प्रभावित कर रही हैं। यह व्यापक शोध लगभग 3 करोड़ व्यक्तियों से जुड़े 51 अध्ययनों पर आधारित है। ये निष्कर्ष भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से चिंताजनक हैं, जहाँ वायु प्रदूषण का स्तर दुनिया में सबसे अधिक है। अगर धनी और विकसित देश भी प्रदूषण के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों से जूझ रहे हैं, तो भारत लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। वायु प्रदूषण से निपटना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि प्रदूषित हवा के नियमित संपर्क में रहने से मनोभ्रंश एवं स्मृति-लोप का खतरा काफी बढ़ जाता है, यह एक ऐसी प्रगतिशील स्थिति है जो स्मृति और संज्ञानात्मक क्षमताओं को क्षीण कर देती है। दुनिया भर में, लगभग 5.74 करोड़ लोग पहले से ही मनोभ्रंश से प्रभावित हैं। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई न किए जाने पर, यह संख्या 2050 तक तिगुनी होकर 15.28 करोड हो सकती है। मनोभ्रंश अर्थात डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का दुनिया में बढ़ता खतरा इतना बड़ा है कि आगामी पच्चीस वर्ष में इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की संख्या तीन गुना हो जाएगी। शोधकताओं ने वायु प्रदूषण में खासकर कार से निकलने वाले धुएं या उत्सर्जन को गंभीर माना है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण में रहने वाले लोगों के मस्तिष्क की कार्यक्षमता में एक दशक तक की गिरावट देखी जा सकती है, उदाहरण के लिए, लगातार जहरीली हवा में सांस लेने वाला 50 वर्षीय व्यक्ति 60 वर्षीय व्यक्ति के समान संज्ञानात्मक क्षमता प्रदर्शित कर सकता है।

वायु प्रदूषण का सबसे पहला असर फेफड़ों और दिल पर पड़ता है, लेकिन यह वहीं तक सीमित नहीं रहता। हवा में मौजूद ये छोटे-छोटे कण हमारी सांस के जरिए खून में चले जाते हैं और फिर सीधे दिमाग तक पहुंच जाते हैं। इससे-याद रखने की क्षमता कमजोर होती है। ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। सीखने और नई बातें याद रखने में दिक्कत

होती है। कुछ मामलों में डिप्रेशन यानी अवसाद की संभावना बढ़ जाती है।

द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में पाया गया कि पीएम 2.5 (सूक्ष्म कण पदार्थ) में प्रति घन मीटर 10 माइक्रोग्राम की वृद्धि से स्मृति संबंधी बीमारियों का खतरा 17 प्रतिशत बढ़ जाता है। वाहनों के धुएँ और जलती हुई लकड़ी से निकलने वाले ब्लैक कार्बन में एक माइक्रोग्राम की भी वृद्धि से यह खतरा 13 प्रतिशत बढ़ जाता है। ये सूक्ष्म कण हमारे श्वसन और परिसंचरण तंत्र को दरकिनार कर मस्तिष्क तक पहुँच सकते हैं और सूजन व ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा कर सकते हैं, जिससे अंततः न्यूरॉन्स को नुकसान पहुँचता है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। प्रदूषित हवा न केवल फेफड़ों और हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है,

बल्कि याददाश्त, एकाग्रता, सीखने और भावनात्मक स्थिरता को भी कमजोर करती है। अध्ययनों से पता चला है कि उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे स्वच्छ वातावरण में रहने वालों की तुलना में स्कूल की परीक्षाओं में खराब प्रदर्शन करते हैं। प्रदूषित हवा के संपर्क में आने वाले वयस्क अक्सर चिड़चिड़ापन, थकान और यहाँ तक कि अवसाद का अनुभव करते हैं। उनकी उत्पादकता और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।

प्रदूषण से प्रेरित स्मृति हानि का प्रभाव केवल व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, यह शैक्षिक परिणामों, कार्यस्थल की दक्षता और सामाजिक निर्णय लेने को भी प्रभावित करता है। आँकड़े दशार्ते हैं कि उच्च-पीएम क्षेत्रों में लोग मौखिक प्रवाह, तर्क, सीखने और स्मृति परीक्षणों में कम अंक प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा का एक पूरा वर्ष गँवाने के समान है। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि कैसे किराने की खरीदारी जैसे नियमित कार्यों में संज्ञानात्मक विकर्षण प्रदूषण के संपर्क में आने से बढ़ जाता है। वृद्ध और कम शिक्षित व्यक्ति विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं, अक्सर रोजमर्रा के कार्य करने की क्षमता खो देते हैं और दूसरों पर अधिक निर्भर हो जाते हैं।

बढ़ते खतरे के बावजूद, चिकित्सा विज्ञान वर्तमान में मनोभ्रंश का कोई निश्चित इलाज नहीं देता है। मौजूदा उपचार सीमित और अक्सर अप्रभावी होते हैं, जिससे मरीज

धीरे-धीरे अपनी याददाश्त और स्वतंत्रता खो देते हैं। अध्ययन के सह-प्रमुख लेखक, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉ. क्रिस्टियन ब्रेडल इस बात पर जोर देते हैं कि मनोभ्रंश की रोकथाम केवल स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी नहीं है। शहरी नियोजन, परिवहन नीतियां और पर्यावरणीय नियम, सभी इस संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायु प्रदूषण न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि सामूहिक सोच, जीवनशैली विकल्पों और पर्यावरणीय निर्णयों को भी विकृत करता है। बड़े पैमाने पर, यह शैक्षिक उपलब्धि में कमी, उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य सेवा के बढ़ते बोझ और गहरी होती आर्थिक असमानताओं में योगदान देता है। वाशिंगटन में 12 लाख लोगों पर किए गए एक अलग अध्ययन से पता चला है कि जंगल की आग के धुएँ के संपर्क में आने से, जो पीएम 2.5 के स्तर को बढ़ाता है, मनोभ्रंश का खतरा 18-21 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक और व्यापक समीक्षा (51 अध्ययनों में 2.9 करोड़ लोगों पर) ने पुष्टि की कि पीएम 2.5 के संपर्क में आने से मनोभ्रंश का खतरा 13-17 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। विज्ञान स्पष्ट है कि ये सूक्ष्म कण श्वसन तंत्र और मस्तिष्क में गहराई तक प्रवेश करते हैं, मस्तिष्क के कार्य को बाधित करते हैं और मानसिक गिरावट को तेज करते हैं।

हाल ही में चीन में हुए एक शोध में भी पीएम और नाइट्रोजन ऑक्साइड के संपर्क को मध्यम आयु वर्ग और वृद्ध लोगों में संज्ञानात्मक क्षमता में कमी, विशेष रूप से कार्यशील स्मृति में कमी से जोड़ा गया है। यह एक बढ़ता हुआ संकट है जिसके प्रभाव न केवल व्यक्तियों पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ रहे हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वायु प्रदूषण अब केवल खांसी या सांस की बीमारी तक सीमित नहीं है, यह चुपचाप हमारी स्मृति, संज्ञानात्मक कार्यों और मानसिक स्वास्थ्य पर हमला कर रहा है। लोग मानसिक थकान, अवसाद या चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। सामूहिक स्तर पर, शिक्षा और उत्पादकता में गिरावट, स्वास्थ्य पर बढ़ता बोझ और आर्थिक असमानता बढ़ती है। अगर तत्काल और निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और बिगड़ेगी। वायु प्रदूषण शरीर में हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है जो कोशिकाओं, प्रोटीन और डीएनए को नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे मनोभ्रंश जैसी तंत्रिका संबंधी बीमारियों का मार्ग प्रशस्त होता है। उत्साहजनक रूप से, शोध बताता है कि वायु प्रदूषण को कम करने से स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और जलवायु क्षेत्रों में दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं। इससे मरीजों, परिवारों और देखभाल करने वालों पर बोझ भी कम होगा। अब हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि हम न केवल अपने फेफड़ों, बल्कि अपने दिमाग की भी रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं?

स्कूल छोड़ती बेटियां: संसाधनों की कमी या सामाजिक चूक?

प्रियंका सौरभ

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा हर गली-चौराहे, सरकारी इमारतों और बैनरों पर चमकता है, लेकिन यह नारा उन गाँवों और बस्तियों तक नहीं पहुंच पाता जहां बेटियाँ रोज स्कूल छोड़ रही हैं। हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की 39.4% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं, यह हमारे सामाजिक ढांचे पर एक कठोर टिप्पणी है।

घर से स्कूल की दूरी, सुरक्षित परिवहन की कमी, उच्च माध्यमिक विद्यालयों का अभाव, शौचालयों की स्थिति और सामाजिक असुरक्षा झ ये सारी बातें किसी शोधपत्र की विषयवस्तु नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत हैं जिनसे रोज हजारों बच्चियाँ जूझ रही हैं। और अंततः उन्हें शिक्षा से हाथ धोना पड़ता है। सरकारी आंकड़े भले ही बढ़े हुए नामांकन दिखाते हों, लेकिन हकीकत यह है कि नामांकन के बाद लड़कियाँ स्कूल तक टिक नहीं पातीं।

एक आम ग्रामीण परिदृश्य को देखें। पाँचवीं तक की स्कूल तो आसपास है, लेकिन आठवीं के बाद विद्यालय दूर है। परिवहन की कोई सुविधा नहीं। न बस, न साइकिल, न ही कोई महिला सहकर्मी या मार्गदर्शक। माता-पिता अपनी बेटी को पाँच किलोमीटर दूर अकेले भेजने से डरते हैं। उन्हें चिंता होती है कि रास्ते में कोई छेड़छाड़ न हो, कोई हादसा न हो। उस चिंता में स्कूल जाना बंद हो जाता है।

शौचालयों की बात करें तो यह सिर्फ सुविधा नहीं, आत्मसम्मान और स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। किशोरावस्था में लड़कियाँ उन परिवर्तनों से गुजरती हैं, जहाँ एक स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय उनकी शिक्षा की निरंतरता तय कर सकता है। लेकिन अधिकांश सरकारी स्कूलों में या तो शौचालय हैं ही नहीं, या हैं तो गंदे, असुरक्षित, या क्षतिग्रस्त। माता-पिता के लिए यह एक और कारण बन जाता है अपनी बेटियों को स्कूल से हटाने का।

सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। जिन स्कूलों में कोई महिला शिक्षक नहीं होतीं, कोई सीसीटीवी कैमरा या गार्ड नहीं होता, वहाँ किशोर लड़कियों को भेजना आज भी माता-पिता के लिए जोखिम उठाने जैसा है। यह डर केवल अव्यवस्था से नहीं, समाज की असंवेदनशीलता से भी उपजा है। आए दिन होने वाली घटनाएं, समाचारों में आती छेड़छाड़ की खबरें इस भय को और गहरा करती हैं।

इन सबके अलावा शिक्षा को लेकर समाज की प्राथमिकताएं भी स्पष्ट नहीं हैं। एक लड़का पढ़े तो 'परिवार का भविष्य' बनता है, लेकिन लड़की पढ़े तो ह्यशादी की उम्र निकलने का डर' पैदा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह मानसिकता अब भी गहराई से मौजूद है। लड़कियों की शिक्षा को 'लाभ' से ज्यादा 'खर्च' माना जाता है।

अब यदि इन परिस्थितियों में एक बेटी स्कूल छोड़ दे, तो क्या इसमें उसकी गलती है? या यह एक सामूहिक चूक है – व्यवस्था की, समाज की, और हमारी?

इस स्थिति का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, ठोस क्रियान्वयन से होगा। सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हर गाँव से तीन किलोमीटर के दायरे में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो। यह बुनियादी शैक्षिक ढांचा हर बच्चे का अधिकार है।

परिवहन की सुविधा उतनी ही जरूरी है जितनी शिक्षक की उपस्थिति। यदि बच्चियाँ स्कूल नहीं पहुँच पाएंगी तो पढ़ेंगी कैसे? सरकार को स्कूल वैन, छात्रा साइकिल योजना या सार्वजनिक परिवहन में ह्यस्कूल पास' जैसे विकल्प सुनिश्चित करने होंगे।

हर स्कूल में स्वच्छ और उपयोगी शौचालयों की अनिवार्यता केवल ह्यस्वच्छ भारत मिशन' का हिस्सा नहीं, बल्कि ह्यबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के सच्चे मर्म का आधार होना चाहिए। महिला कर्मचारियों की नियुक्ति, नियमित निरीक्षण और साफ-सफाई के लिए स्थानीय प्रशासन को उत्तरदायी बनाया जाए।

सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्कूल में महिला शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाई जाए। सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरा और स्कूल परिसर में अभिभावकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। यह कदम न केवल बेटियों को सुरक्षा का भरोसा देगा, बल्कि अभिभावकों को मानसिक शांति भी।

इसके साथ ही स्कूलों के भवन और अधोसंरचना को केवल औपचारिकता के लिए नहीं, गुणवत्ता के साथ विकसित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान – ये सब स्कूल के मानक हिस्से होने चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बिंदु डिजिटल शिक्षा है। महामारी ने दिखा दिया कि जिनके पास मोबाइल, इंटरनेट और बिजली नहीं, वे पढ़ाई से बाहर हो जाते हैं। ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और उपकरण की उपलब्धता अब विलासिता नहीं, अनिवार्यता है। शिक्षा विभाग को उन लड़कियों की नियमित सूची बनानी चाहिए जो स्कूल छोड़ चुकी हैं। उनके घर जाकर कारण जानना, उन्हें वापस लाने के लिए प्रेरित करना, और माता-पिता को विश्वास में लेना प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

साथ ही समाज को भी आत्मावलोकन करना होगा। हम अपनी बेटियों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं – नौकरी के लिए, शादी के लिए या आत्मनिर्भरता के लिए? जब तक

समाज का जवाब अस्पष्ट रहेगा, तब तक समाधान भी अधूरा रहेगा।

प्रशासन, समाज और परिवार को मिलकर यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित न हो। इसका अर्थ है केवल विद्यालय खुलवाना नहीं, बल्कि उसमें बेटी के जाने और टिके रहने की पूरी ज़िम्मेदारी लेना। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अगर केवल बैनर की पंक्ति नहीं रहना है तो इसे पंचायतों, स्कूल समितियों, शिक्षक संगठनों, अभिभावकों और छात्रों के साझा प्रयास में बदलना होगा। तभी एक ऐसा समाज बनेगा, जहाँ कोई भी बेटी पढ़ाई से वंचित नहीं होगी।

एआई का विस्तार या नौकरी का संकुचन

राष्ट्र समाज

भारत जैसे युवाओं वाले और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में तकनीकी विकास के प्रति उत्साह हमेशा गहरा रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसी तकनीकें समाज, राष्ट्र और अर्थव्यवस्था में तीव्र बदलाव की सारथि बनी हैं। हर वर्ग और क्षेत्र ने इस परिवर्तन को आशा एवं सकारात्मकता के साथ अपनाया है, इस उम्मीद में कि तकनीकी तरक्की के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। लेकिन हाल ही में आईटी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा ने इस उम्मीद पर पानी फेर दिया और इसे बड़ा झटका दिया है। निस्संदेह, छंटनी का यह फैसला आईटी क्षेत्र में आसन्न संकट की आहट को ही दशार्ता है। छंटनी बाबत टीसीएस की दलील है कि इन नौकरियों में कटौती कौशल की कमी और अपने विकसित होते व्यावसायिक मॉडल में कुछ कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने में असमर्थता के चलते की गई है। हालांकि, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का दावा है कि इस कदम के पीछे एआई से प्रेरित उत्पादकता वृद्धि नहीं है। यह संख्या कंपनी के कुल कार्यबल का लगभग 2 प्रतिशत है, और मुख्यतः मध्यम और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों को प्रभावित करेगी।

एआई और ऑटोमेशन केवल तकनीक नहीं हैं, वे कार्य संस्कृति, संगठन संरचना और मानव संसाधन नीति को मूल रूप से बदल रहे हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार, एआई से प्रेरित उत्पादकता और लागत में कटौती की प्रवृत्ति बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर, एमेजोन ने 30,000 सॉफ्टवेयर एप्लिकेशनों को एआई की मदद से मात्र छह महीनों में अपग्रेड किया, जो कार्य सामान्यतः डेवलपर्स को एक वर्ष लगता। इससे कंपनी को लगभग 250 मिलियन डॉलर की बचत हुई। इसी प्रकार, माइक्रोसोफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों में कोडिंग का 20 से 50 प्रतिशत कार्य एआई से कराया जा रहा है। भारत में एआई का प्रसार अभी अमेरिका या यूरोप की तुलना में सीमित है, लेकिन इसकी गति तीव्र है। देश के स्टार्टअप और आईटी क्षेत्र में छंटनियों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार, केवल वर्ष 2025 के शुरूआती पांच महीनों में भारत में 3600 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया, जिसमें एआई आधारित लागत नियंत्रण एक प्रमुख कारण रहा। यह स्पष्ट करता है कि एआई के कारण दोहराव वाले कार्यों की उपयोगिता घट रही है और उनकी जगह स्मार्ट तकनीक ले रही है। मौजूदा समय में यह कदम लागत-अनुकूलन पहलों के चलते अन्य आईटी सेवा कंपनियों में भी छंटनी को बढ़ावा दे सकता है। इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कारोबार के नियमों में मौलिक बदलाव के चलते, भविष्य के लिये तैयार रहना हर व्यावसायिक उद्यम के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। इस नई हकीकत को देखते हुए, अनेक सवाल सबसे ज्यादा विचलित करने वाले बनकर उभर रहे हैं कि क्या यह तकनीकी बदलाव अनिवार्य रूप से कर्मचारियों की कीमत पर होना चाहिए? एआई युग में नौकरी की अनिश्चितता क्या

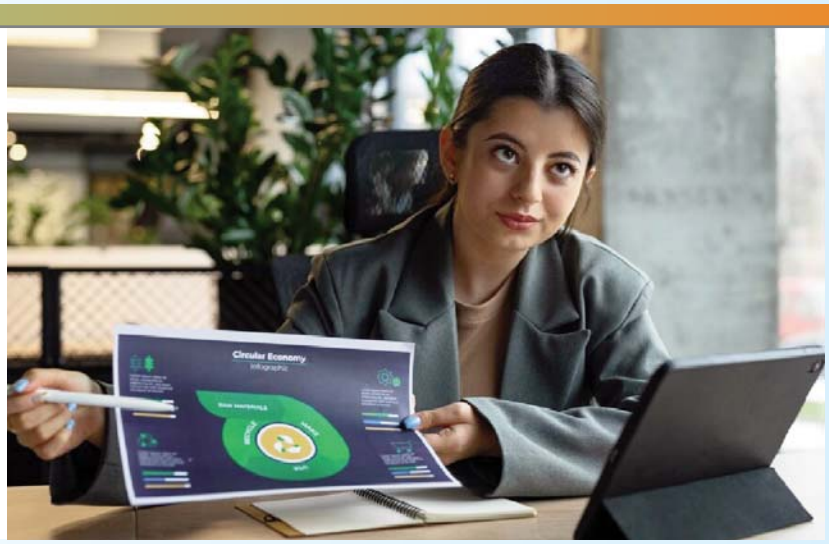

तकनीक विकास के नाम पर विस्थापन नहीं है? छंटनी की चपेट में युवाओं का भविष्य क्या तकनीकी प्रगति के नाम पर मानव श्रम पर आघात नहीं है? क्या स्मार्ट मशीनें के दौर में भारत में रोजगार को नई चुनौती और इंसानों को हताशा में धकेलना नहीं है? एआई का विस्तार यानी नौकरी का संकुचन क्या भारत के लिए बड़ी चेतावनी की घड़ी बन रहा है?

इन प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी का संकट किसी से छिपा नहीं है। देश में श्रमबल का कौशल विकास धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में आईटी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लेकिन टीसीएस के इस फैसले से आईटी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे उन लाखों छात्रों और डिग्री लेकर निकल रहे उत्साही इंजीनियरों में निराशा व्याप्त होगी। भारत में बढ़ता रोजगार संकट केंद्र सरकार से निरंतर हस्तक्षेप की मांग करता है। हाल ही में हरियाणा में हुई एक परीक्षा में लाखों युवाओं की भागीदारी इस बात का संकेत है कि रोजगार की मांग कितनी व्यापक और अवसर कितने सीमित हैं। देश ही नहीं, दुनिया में रोजगार का संकुचन एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। गोल्डमैन सोच्स की रिपोर्ट के अनुसार, एआई और ऑटोमेशन के चलते दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। विश्व आर्थिक मंच का आकलन है कि 2030 तक 92 मिलियन नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन उसी अवधि में 170 मिलियन नई नौकरियां भी पैदा होंगी। यह एक दोधारी तलवार है, जो बदलेगा, बचेगा; जो रुकेगा, वो हाशिए पर जाएगा।

टीसीएस का दावा है कि छंटनी का निर्णय भविष्य की जरूरतों के अनुसार संगठन को ढालने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का ध्यान एआई में निवेश, नए बाजारों में प्रवेश, ग्राहक अनुभव सुधार और कार्यबल मॉडल के पुनर्गठन पर केंद्रित है। हालांकि, यह तर्क उन हजारों कर्मचारियों की व्यथा को शांत नहीं कर सकता जिनकी आजीविका पर इसका सीधा प्रहार हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से न केवल कंपनी के भीतर बल्कि समूचे आईटी क्षेत्र में आशंका, आक्रोश एवं अनिश्चितता का माहौल बन गया है। खासकर युवाओं और आईटी की पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए यह एक मानसिक झटका है। तकनीकी शिक्षा में दाखिले बढ़ रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं। यह असंतुलन देश की सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टें बताती हैं कि विश्व स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत नौकरियां एआई के कारण जोखिम में हैं। भारत में अनुमान है कि 2025 तक 12-18 मिलियन नौकरियां एआई आधारित ऑटोमेशन के चलते प्रभावित हो सकती हैं, विशेषकर आईटी और बीपीओ क्षेत्रों में। एटेमबर्ग के संस्थापक के अनुसार, भारत में 40-50 प्रतिशत व्हाइट कॉलर नौकरियां एआइ से प्रभावित होने के कगार पर हैं, जिससे देश के मध्यवर्ग की आर्थिक स्थिरता को गहरा झटका लग सकता है।

निश्चित तौर पर एआई और तकनीकी बदलाव अपरिहार्य हैं। सवाल यह है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं? इसके लिए तीन प्रमुख कदम जरूरी हैं, पहला पुनःकौशल और सतत शिक्षा यानी कार्यबल को भविष्य के अनुरूप प्रशिक्षित करना होगा। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एथिक्स, सॉफ्ट स्किल्स जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण अनिवार्य बनाना होगा। दूसरा नीतिगत समर्थन यानी सरकार को एआई नीति, डिजिटल समावेशन और श्रमिक सुरक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने होंगे। रोजगार खोने वालों के लिए पुनर्वास योजनाएं और स्किल अपडेट कार्यक्रम आवश्यक हैं। तीसरा सांस्कृतिक और सामाजिक समायोजन यानी एआई को केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसे अपनाने में पारदर्शिता, विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाना होगा। तकनीकी बदलाव नई संभावनाएं लेकर आते हैं, लेकिन वे अनायास ही चुनौतियां भी खड़ी करते हैं। टीसीएस की छंटनी से जो संदेश मिलता है वह यही है कि एआई युग में केवल वही टिकेगा जो परिवर्तनशील रहेगा। अब समय आ गया है कि हम तकनीक को केवल उपकरण नहीं, बल्कि नीति और जीवनशैली का हिस्सा मानें। सतत सीखना, अनुकूलन और सामाजिक न्याय, यही तीन स्तंभ हैं, जो भारत को इस तकनीकी क्रांति में न केवल जीवित, बल्कि अग्रणी बना सकते हैं।

दुनिया की लाखों जिंदगियां में जहर घोलता अकेलापन

ललित गर्ग

हर छठा व्यक्ति अकेला है'-यह निष्कर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ताजा रिपोर्ट का है, जिसने पूरी दुनिया को चिन्ता में डाला है एवं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम कैसी समाज-संरचना कर रहे हैं, जो इंसान को अकेला बना रही है। निश्चित ही बढ़ता अकेलापन कोई साधारण सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है, जो व्यक्तियों, समाजों, और व्यावसायिक संस्थानों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। दुनिया के करोड़ों लोग टूटे रिश्तों व संवादहीनता की स्थितियों में नितांत खामोशी का जीवन जी रहे हैं। गौर करे तो इंसान के भीतर की ये खामोशी लाखों जिंदगियां में महामारी के रूप में जहर घोल रही है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। वृद्ध तो पहले से ही सामाजिक एवं पारिवारिक विसंगतियों में उपेक्षित है। निश्चय ही जीवन की विसंगतियां एवं विषमताएं बढ़ी हैं। कई तरह की चुनौतियां सामने हैं। पीढ़ियों के बीच का अंतराल विज्ञान व तकनीक के विस्तार के साथ तेज हुआ है।

डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की लगभग 16 प्रतिशत आबादी आज किसी न किसी रूप में अकेलेपन, सामाजिक अलगाव या भावनात्मक दूरी का शिकार है। यह स्थिति केवल वृद्धजनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवाओं, कामकाजी पेशेवरों, और यहां तक कि बच्चों तक फैल चुकी है। डिजिटल युग में जहां सब कुछ 'कनेक्टेड' लगता है, वहीं इंसानी रिश्तों में एक अदृश्य दूरी, कृत्रिमता और आत्मीयता का अभाव देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में हम जितने

अधिक जुड़े हैं, उतने ही भावनात्मक रूप से अकेले हो गए हैं। व्यक्तिवादी सोच, सामाजिक दुष्प्रभाव एवं रिश्तों की बिखरती दीवारों में अकेलेपन का घातक प्रभाव सामाजिक ढांचे पर गहरे रूप में पड़ रहा है। पारिवारिक संबंधों में दरारें, विवाहों में असंतोष, और तलाक की बढ़ती दरें इसकी साफ निशानी हैं। युवा पीढ़ी में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति और नशे की ओर झुकाव एक चिंताजनक ट्रेंड बन गया है। बुजुर्गों में अकेलेपन से उत्पन्न अल्जाइमर, डिमेंशिया और अन्य मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं।

अकेलापन केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक विफलता का संकेत है। जब हम तकनीक, दौड़ और स्वार्थ में इतने उलझ जाते हैं कि किसी के पास 'सुनने का समयह्व नहीं रहता, तब अकेलापन जन्म लेता है। अब समय आ गया है कि हम फिर से रिश्तों, संवाद और करुणा की दुनिया की ओर लौटें। अन्यथा अकेलापन, उदासी और असंतुष्टि की भावनाएं कचोटती रहेगी। मानो खुद के होने का एहसास, कोई इच्छा ही ना बची हो। तब छोटी-छोटी चीजों में छिपी खूबसूरती नजर ही नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग जिंदा हैं, पर जीवित होने के जादुई एहसास को कम ही छू पाते हैं। सोच के भौतिकवादी एवं सुविधावादी होने से हमारी आकांक्षाओं का आसमान ऊंचा हुआ है। लेकिन यथार्थ से साम्य न बैठा पाने से कुंठा, हताशा व अवसाद का विस्तार हो रहा है। जिसके चलते निराशा हमें एकाकीपन या अकेले होने की ओर धकेल देती है। निश्चित ही सोशल मीडिया का क्रांतिकारी ढंग से विस्तार हो रहा है। लेकिन इसकी हकीकत आभासी है, कृत्रिम है, दिखावटी है। हर कोई सोशल मीडिया मंचों पर हजारों मित्र होने का दावा करता है, लेकिन ये मित्र कितने संवेदनशील है? कितने करीब है? इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही है, यथार्थ के जीवन में व्यक्ति बिल्कुल अकेला एवं गुमशुम होता है। आभासी मित्रों का कृत्रिम संवाद हमारी जिंदगी के सवालों का समाधान नहीं दे सकता, अकेलापन दूर नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कृत्रिम रिश्ते हमारे वास्तविक रिश्तों के ताने-बाने को मजबूत नहीं कर सकते।

विडंबना यह है कि कृत्रिमताओं के चलते कहीं न कहीं हमारे शब्दों की प्रभावशीलता में भी कमी आई है। जिससे व्यक्ति लगातार एकाकी जीवन की ओर उन्मुख होना लगा है। हमारे संयुक्त परिवारों का बदलता स्वरूप एवं एकल परिवारों का बढ़ता प्रचलन भी इसके मूल में है। पहले घर के बड़े बुजुर्ग किसी झटके या दबाव को सहजता से झेल जाते थे। सब मिल-जुलकर आर्थिक व सामाजिक संकटों का मुकाबला कर लेते थे। लेकिन अब बुजुर्ग एकाकीपन एवं अकेलापन से जूझ रहे है। केरल में इसी तरह के वृद्ध-संकट को महसूस करते हुए वहां की सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया है, जो एक सूझबूझभरा कदम है। आज वृद्धों को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, दुर्व्यवहार, तिरस्कार, कटुक्तियां, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर-उधर भटकने का गम हरदम सालता रहता। वृद्ध समाज इतना कुंठित, अकेला एवं उपेक्षित क्यों है, एक अहम प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार अनेक स्वस्थ एवं आदर्श समाज-निर्माण की योजनाओं को आकार देने में जुटी है, उन्हें वृद्धों को अकेलेपन को लेकर भी चिन्तन करते हुए वृद्ध-कल्याण योजनाओं को लागू करना चाहिए, ताकि वृद्धों की प्रतिभा, कौशल एवं अनुभवों का नये भारत-सशक्त भारत के निर्माण में समुचित उपयोग हो सके एवं आजादी के अमृतकाल में अकेलापन एक त्रासदी न बन सके।

कामकाजी परिस्थितियों का लगातार जटिल होना एवं महंगी होती जीवनशैली ने अकेलापन के संकट को गहरा बनाया है। उन परिवारों में यह स्थिति और जटिल है, जहां पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं और बच्चे हॉस्टलों व बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी काम का बोझ इंसानों को अकेला बना रहा है। कार्यालयों और कार्यस्थलों पर भी अकेलापन एक गंभीर चुनौती बन रहा है। कर्मचारी भावनात्मक

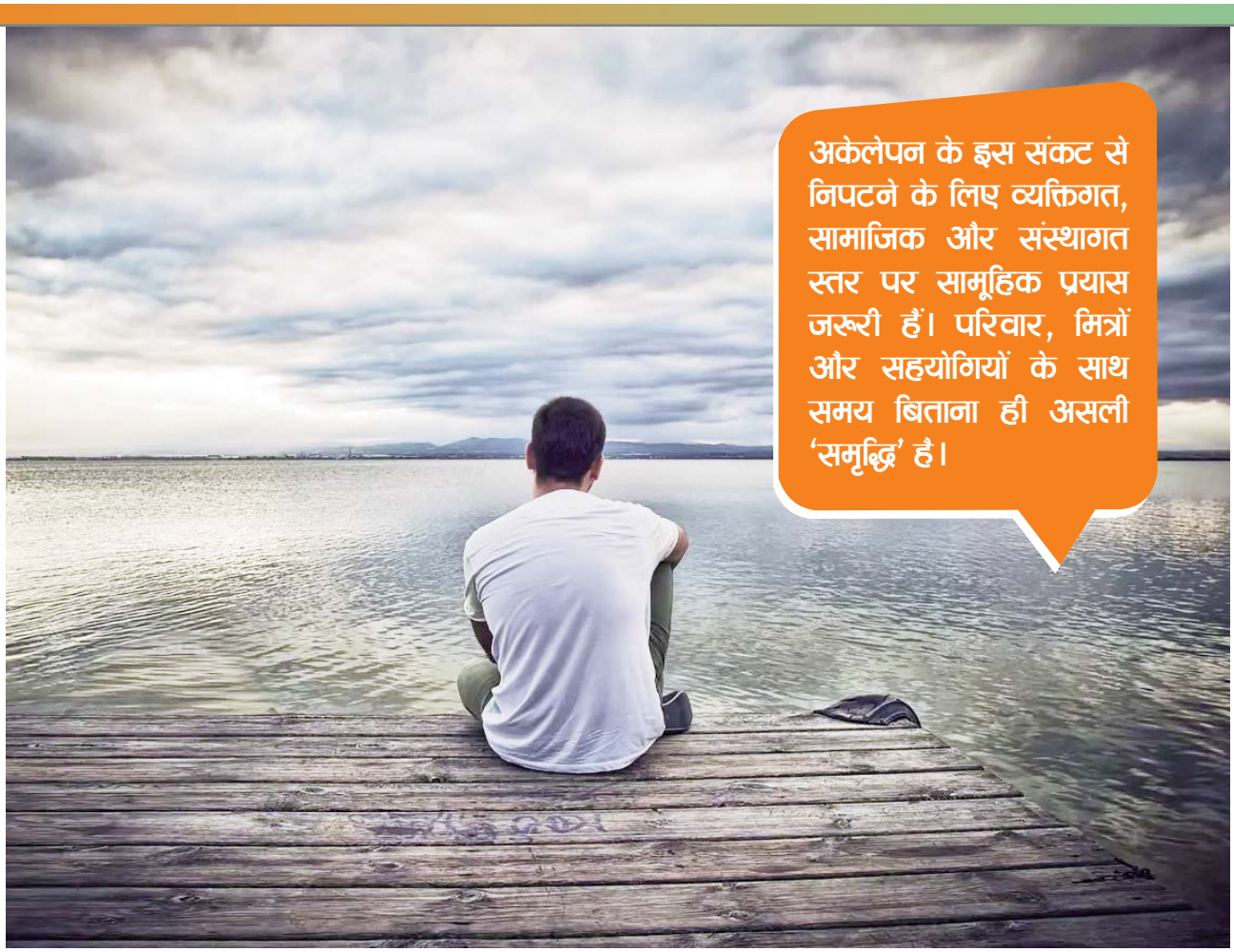

जुड़ाव की कमी के कारण कार्य में रुचि नहीं लेते। टीम वर्क, इनोवेशन और सहयोग पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। अकेलापन लंबे समय तक बना रहा तो यह बर्नआउट, कार्य से असंतोष और कर्मचारी त्यागपत्र जैसी स्थितियों को जन्म देता है। इससे उत्पादकता में भी गिरावट आती है। मेकिन्से और डेलॉइट जैसी वैश्विक कंसल्टिंग फर्म्स की रिपोर्टें दशार्ती हैं कि अकेलापन कर्मचारियों की उत्पादकता को 15-20 प्रतिशत तक घटा सकता है, जिससे कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है।

अकेलेपन के इस संकट से निपटने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ समय बिताना ही असली 'समृद्धि' है। कंपनियों और संस्थानों में कर्मचारियों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझने वाला नेतृत्व चाहिए। डिजिटल संवाद की जगह आमने-सामने संवाद, 'वर्क फ्रॉम होम' की जगह ह्यवर्क विद कम्युनिटी' को प्राथमिकता देनी होगी। ऑफिसों और समाज में काउंसलिंग, समूह चर्चा, मेडिटेशन, और योग को प्रोत्साहन दिया जाए। सरकारों को अकेलेपन को एक जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देनी चाहिए और सामाजिक समावेश के लिए ठोस कार्यक्रम चलाने चाहिए।

डब्ल्यूएचओ का वह आंकड़ा भी चौंकाता है कि अकेलापन हर साल तकरीबन आठ लाख लोगों की जीवन लीला समाप्त कर रहा है। जो यह दशार्ता है कि व्यक्ति न केवल समाज व अपने कार्यालयी परिवेश से अलग-थलग हुआ है, बल्कि वह परिवार से भी कटा है। पिछले दिनों देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने कार्यालयों में काम के घंटे बढ़ाने का आग्रह किया था। एक उद्यमी ने तो यहां तक कहा कि क्या जरूरी है कि घर में रहकर पत्नी का ही चेहरा देखा जाए। यह एक संवेदनहीन एवं बेहूदा प्रतिक्रिया थी। दरअसल, लोगों में यह आम धारणा बलवती हुई है कि जिसके पास पैसा है तो वह सबकुछ कर सकता है। जिसके चलते उसने आस-पड़ोस से लेकर कार्यस्थल पर सीमित पहुंच बनायी है। यही वजह है कि हमारे इर्द-गिर्द की भीड़ और ऑनलाइन जिंदगी के हजारों मित्रों के बावजूद व्यक्ति अकेलेपन को जीने के लिये अभिशप्त है।सही बात ये है कि लोग किसी के कष्ट और मन की पीड़ा के प्रति संवेदनशील व्यवहार नहीं करते। हर तरफ कृत्रिमताओं का बोलबाला है। हमारे मिलने-जुलने वाले त्योहार भी अब दिखावे व कृत्रिम सौगातों की भेंट चढ़ गए हैं। हमें उन कारकों पर मंथन करना होगा, जिनके चलते व्यक्ति निजी जीवन में लगातार अकेला या एकाकी होता जा रहा है। असल में अकेलापन तभी मिटेगा जब हम फिर से इंसान बनेंगे-संवेदनशील, सजीव, संवाद और रिश्तों की गर्माहटत से भरे हुए।

Haldiram's
Banao
CHATPATE
PAL AUR
MEETHI
YAADEIN!
Shop Online@www.haldiramsonline.com

पतियों को छोड़ रही हैं आधुनिक औरतें

डॉ. प्रियंका सौरभ

बिना किसी कारण, बिना किसी उत्पीड़न के यदि कोई पत्नी केवल नौकरी लगने के बाद पति को अस्वीकार कर दे, तो यह न सशक्तिकरण है,न स्वतंत्रता यह एक सामाजिक अपराध है।

एक समय था जब पति-पत्नी का रिश्ता त्याग, प्रेम और परस्पर समर्पण का प्रतीक होता था। विवाह सिर्फ सामाजिक अनुबंध नहीं, एक गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती थी। लेकिन आज की आधुनिकता, शिक्षा और तथाकथित 'अधिकार चेतना' ने इस पवित्र रिश्ते को भी स्वार्थ की भट्ठी में झोंक दिया है। आज देश में तेजी से बढ़ते ऐसे मामलों पर चिंता जाहिर हो रही है जहां एक पति सालों मेहनत करके, मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ाता है, उसके सपनों को पंख देता है, और जैसे ही उसकी सरकारी नौकरी लगती है – वह उसी पति से कहती है: 'आप कौन जी?'

यह सवाल अकेले एक पुरुष से नहीं पूछा जा रहा, यह सवाल उस समूचे त्याग से पूछा जा रहा है, जो एक रिश्ते को निभाने में लगाया गया था। यह सवाल उस व्यवस्था पर भी है, जिसने शिक्षा को अधिकार तो दिया, मगर ज़िम्मेदारी नहीं सिखाई। यह सवाल कानून से भी है, जिसने स्त्री को संरक्षण तो दिया, पर रिश्तों को निभाने की नैतिकता सिखाने का प्रयास नहीं किया। आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ एक और विचारधारा ने समाज में गहराई से जड़ें जमा ली हैं 'खुद को पहले रखो', 'रिश्ते बोझ हैं', 'स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी बंधन से मुक्त होना'। यह सोच, विशेषकर महिलाओं को यह सिखा रही है कि विवाह, पति, परिवार केवल एक सामाजिक औपचारिकता हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर त्यागा जा सकता है। और जब शिक्षा, कानून और समाज का एक वर्ग इस सोच को बढ़ावा देता है, तो परिणाम होता है घर टूटते हैं, विश्वास बिखरता है और पुरुषों का त्याग मजाक बन जाता है।

एक गरीब पति जिसने ईंटें ढोकर, दिहाड़ी लगाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसका फॉर्म भरा, उसकी फीस दी, परीक्षा केंद्र तक छोड़ा, उसके चयन के बाद मिठाई बांटी, वही पति जब दरवाजे पर खड़ा होता है तो पत्नी कहती है 'अब आपकी कोई जरूरत नहीं रही। यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं, यह उस संघर्ष की मौत है जिसमें रिश्ते सांस लेते थे। यह आधुनिकता का वह चेहरा है, जो चमकता तो है, पर भीतर से खोखला है।

बिना किसी कारण, बिना किसी उत्पीड़न के यदि कोई पत्नी केवल नौकरी लगने के बाद पति को अस्वीकार कर दे, तो यह न सशक्तिकरण है,न स्वतंत्रता यह एक सामाजिक अपराध है। यह उन मूल्यों की हत्या है जो भारतीय समाज की नींव हैं। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम उन स्त्रियों की बात नहीं कर रहे जो वाकई उत्पीड़न झेलती हैं, शोषित होती हैं या जिन्हें बचाव की आवश्यकता है। बात उन मामलों की हो रही है जहां कानून और अधिकारों का दुरुपयोग करके एक पत्नी अपने पति को केवल इसलिए छोड़ देती है क्योंकि अब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई है।

कानून ने महिलाओं को जो संरक्षण दिया है, वह आवश्यक है और होना भी चाहिए, लेकिन वह संरक्षण तभी तक पवित्र है जब तक उसका उपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। आज समाज में ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है जहाँ महिलाओं ने झूठे आरोप लगाकर न केवल अपने पतियों को, बल्कि उनके परिवारों को भी जेल भिजवा दिया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और आर्थिक रूप से तबाह कर दिया। क्या यही है 'नवीन भारतह्व का पारिवारिक चेहरा? जब एक लड़की कहती है, 'अब मैं कमाती हूं, मुझे किसी की जरूरत नहींह्व, तो यह स्वतंत्रता नहीं, आत्ममुग्धता है। क्या आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि रिश्तों को छोड़ दिया जाए? क्या नौकरी लगते ही प्रेम और त्याग की कीमत शून्य हो जाती है? क्यों नहीं यह समझाया जाता कि सशक्त स्त्री वह है जो अपनी उड़ान में भी अपने घोंसले को संजोकर रखे, न कि उड़ते ही उसे जला दे?

शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि सोच में परिपक्वता लाना है। दुर्भाग्यवश आज की पढ़ाई ने यह परिपक्वता नहीं दी, बल्कि कई मामलों में आत्मकेंद्रित सोच को जन्म दिया है। आत्मनिर्भरता अगर

स्वार्थ में बदल जाए, तो वह समाज के लिए एक खतरा बन जाती है। पढ़ाई के बाद यदि स्त्री अपने रिश्तों से पलायन करती है, तो यह प्रश्नचिन्ह है उस शिक्षा पर, उस सोच पर, और उस कानून पर जो उसे यह करने की छूट देते हैं। कई बार जब पत्नी पति को छोड़ती है, तब समाज चुप रहता है। महिलाएं इसे अपना अधिकार मानती हैं, और पुरुषों के पास बोलने तक की जगह नहीं होती। अगर कोई पति यह कह दे कि 'मैंने उसे पढ़ाया, बढ़ाया, उसका करियर बनाया', तो उसे कहा जाता है कि 'उसने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, वह अब स्वतंत्र है।' लेकिन जब कोई स्त्री अपने पति के बलिदान से आगे बढ़ती है, तो क्या उस त्याग की कोई कीमत नहीं होती? क्या उसकी कोई भावनात्मक मान्यता नहीं?

यह मानसिकता अब अदालतों तक पहुँच चुकी है। न्यायालयों में ऐसे हजारों केस लंबित हैं जहां पुरुष अपने वैवाहिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रहे हैं, और वर्षों तक एक ऐसे रिश्ते का बोझ ढो रहे हैं जो केवल कागज पर बचा है। वे न तलाक ले सकते हैं, न नया जीवन शुरू कर सकते हैं, और न ही समाज उनकी पीड़ा समझता है।

कई मामलों में तो पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ बाहर से प्रेम संबंध जोड़ लेती हैं, पति से दूरी बना लेती हैं, और फिर कानूनी सुरक्षा के पीछे छिप जाती हैं। जब ऐसे मामलों पर कोई प्रश्न उठाता है, तो उसे 'महिला विरोधी', 'संकीर्ण सोच वाला' या 'पितृसत्तात्मक' कहा जाता है। लेकिन क्या एक समाज को इतना भी अधिकार नहीं कि वह रिश्तों की रक्षा करने वाले पुरुष की आवाज को सुने?

यदि यही मानसिकता चलती रही, तो आने वाले वर्षों में विवाह संस्था ही खोखली हो जाएगी। पुरुष विवाह से डरेंगे, परिवार टूटेंगे, और समाज में अविश्वास की दीवारें खड़ी होंगी। स्त्रियों को यह समझना होगा कि वे केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को निभाने के लिए भी उत्तरदायी हैं। जब कोई पति आपकी फीस भरता है, कोचिंग लगवाता है, हौसला देता है, तब वह केवल पति नहीं, एक मार्गदर्शक, एक सहायक, एक संरक्षक बनता है। और जब आप सफलता पाकर उसे छोड़ देती हैं, तो आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि विश्वास को ठुकरा देती हैं। यह समाज अब और अधिक झूठे केस, दिखावटी आजादी और स्वार्थ की आड़ में तोड़े गए रिश्ते नहीं झेल सकता। अब वक्त आ गया है कि शिक्षा में नैतिक मूल्य जोड़ें, कानूनों में संतुलन लाएं, और समाज में यह संदेश दें कि सशक्तिकरण का अर्थ जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि उसे ईमानदारी से निभाना है। रिश्तों में अधिकार जितने जरूरी हैं, उतने ही जरूरी हैं कर्तव्य। सच्चा सशक्तिकरण वही है जो रिश्तों को तोड़े नहीं, उन्हें और मजबूत करे। क्योंकि अगर नौकरी लगते ही कोई पत्नी अपने पति को कहे 'आप कौन?' तो यह केवल पति की नहीं, पूरे समाज की हार है।

झारखंड आंदोलन के अमर नायक का युगांत

राष्ट्र समाज

झारखंड की धरती का वो सूरज, जिसने आदिवासी समाज को शोषण, सूदखोरी और अन्याय के अंधेरे से निकालकर स्वाभिमान और सम्मान की रोशनी दिखाई, आज सदा के लिए अस्त हो गया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जिन्हें झारखंड का पथ प्रदर्शक कहा जाता था, ने 4 अगस्त 2025 को सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। 81 वर्ष की आयु में उनके निधन ने न केवल झारखंड, बल्कि पूरे देश को एक ऐसी शख्सियत से वंचित कर दिया, जिसने जंगलों से लेकर संसद तक आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ी। शिबू सोरेन एक नेता से कहीं अधिक थे वे एक क्रांति थे, जिन्होंने महाजनों, जमींदारों और शोषक व्यवस्था के खिलाफ उलगुलान की हुंकार भरी। उनकी मशाल ने लाखों आदिवासियों को नई राह दिखाई, और उनकी डुगडुगी की गूंज आज भी झारखंड की माटी में गूंजती है।

11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मे शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष और समर्पण की गाथा है। उनके पिता सोबरन सोरेन एक शिक्षक और गांधीवादी विचारों के व्यक्ति थे, जो उस दौर में महाजनों के आतंक के खिलाफ आवाज उठाते थे। उस समय झारखंड में आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीनें हड़प ली जाती थीं। मेहनत का फल महाजन छीन लेते थे, और आदिवासी समाज गरीबी और शोषण का शिकार था। 27 नवंबर 1957 को सोबरन सोरेन की हत्या ने शिबू के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पढ़ाई छोड़कर उन्होंने शोषण के खिलाफ बगावत का रास्ता चुना। युवा शिबू ने आदिवासी युवाओं को संगठित करना शुरू किया, और यहीं से दिशोम गुरु की यात्रा शुरू हुई, जिसने झारखंड के इतिहास को नया मोड़ दिया।

1970 के दशक में शिबू सोरेन ने धनकटनी आंदोलन की शुरूआत की, जो झारखंड के आदिवासी आंदोलन का स्वर्णिम अध्याय बन गया। इस आंदोलन में आदिवासी युवा तीर-कमान लेकर खेतों की रखवाली करते, और महिलाएं हंसिया लेकर महाजनों की फसल काट लेती थीं। मांदर की थाप पर मुनादी के साथ यह आंदोलन रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, टुंडी, पलमा, तोपचांची और बेरमो जैसे इलाकों में फैल गया। शिबू ने एक नैतिक मर्यादा तय की यह लड़ाई केवल खेतों तक सीमित रहेगी, न महाजनों की महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा, न उनकी अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस अनुशासन ने उनके आंदोलन को न केवल मजबूती दी, बल्कि आदिवासियों में आत्मविश्वास और एकता का संचार किया। धनकटनी आंदोलन ने शिबू सोरेन को आदिवासियों का नायक बना दिया, जो शोषण और सूदखोरी से मुक्ति का प्रतीक बन गए।

4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन ने बिनोद बिहारी महतो और कॉमरेड एके राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की स्थापना की। यह संगठन बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी से प्रेरित था, जिसने 1971 में स्वतंत्रता हासिल की थी। झामुमो का लक्ष्य था झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाना और आदिवासी समाज को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करना। इस संगठन ने न केवल आदिवासियों को एकजुट किया, बल्कि उनकी आवाज को राष्ट्रीय पटल पर बुलंद किया। शिबू की अगुवाई में

झामुमो ने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी, और 2000 में झारखंड के गठन में इसकी ऐतिहासिक भूमिका रही। आज झामुमो झारखंड की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है, जो शिबू के सपनों को जीवित रखती है।

शिबू सोरेन का जीवन आसान नहीं था। पारसनाथ के घने जंगलों में भटकते हुए, पुलिस की गोलियों से बचते हुए, उन्होंने रातें पेड़ों की छांव में गुजारीं। 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया। धनबाद के तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर केबी सक्सेना ने उन्हें सरेंडर के लिए राजी किया। 1976 में धनबाद जेल में बंद शिबू ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। एक महिला कैदी के छठ गीत सुनकर वे भावुक हो गए और जेल में छठ पूजा का आयोजन करवाया। कैदियों ने एक समय का भोजन त्यागकर इसका खर्च जुटाया, और महिला ने पारंपरिक आस्था के साथ पूजा की। यह घटना उनकी मानवीयता और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है।एक अन्य घटना में, पलमा के जंगल में रात के समय पुलिस ने उन्हें घेर लिया। डुगडुगी की आवाज पर आदिवासियों का हुजूम इकट्ठा हो गया, और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। यह था शिबू सोरेन का जनता के साथ अटूट रिश्ता। उनकी डुगडुगी एक संकेत थी, जो आदिवासियों को एकजुट करने की ताकत रखती थी।

शिबू सोरेन के निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने भावुक होकर कहा, 'आज मैं शून्य हो गया हूँ। मेरे पिता दिशोम गुरु झारखंड के सपनों का प्रतीक थे।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, 'शिबू सोरेन जी का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका योगदान आदिवासी सशक्तिकरण और झारखंड आंदोलन में हमेशा याद रखा जाएगा।' कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'दिशोम गुरु ने शोषितों की आवाज बुलंद की। उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी।' झारखंड के विभिन्न हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे, मांदर की थाप पर शोक गीत गाए गए, और उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। सोशल मीडिया पर आम जनता, सामाजिक कार्यकताओं और नेताओं ने उन्हें याद किया। एक यूजर ने लिखा, 'शिबू सोरेन ने हमें सिखाया कि हिम्मत और एकता से कोई भी जंग जीती जा सकती है।'

शिबू सोरेन का निधन झारखंड के लिए एक युग का अंत है। लेकिन उनकी मशाल, जो उन्होंने आदिवासियों के हक के लिए जलाई, कभी नहीं बुझेगी। धनकटनी आंदोलन से लेकर झामुमो के गठन और अलग झारखंड के सपने को साकार करने तक, उनका हर कदम एक प्रेरणा है। उनकी डुगडुगी की गूंज और मांदर की थाप झारखंड की माटी में हमेशा गूंजती रहेगी। उनकी विरासत न केवल हेमंत सोरेन, बल्कि हर उस व्यक्ति में जीवित है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस रखता है।दिशोम गुरु की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सपनों का झारखंड शोषणमुक्त, सशक्त और समृद्ध साकार हो। शिबू सोरेन ने न केवल झारखंड को एक नई पहचान दी, बल्कि लाखों आदिवासियों को जीने का हौसला दिया। उनकी लड़ाई, उनका साहस और उनका समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें !

एक्टिंग छोड़ेंगी दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण ने एक फैसले से अपने फैंस को चौंका दिया है। लंबे समय से चर्चा में रही फिल्म 'द इंटर्न' के भारतीय रीमेक में वह अब एक्टिंग नहीं करेंगी। इसके बजाय दीपिका इस फिल्म को बतौर प्रोड्यूसर आगे बढ़ाएंगी। दीपिका के इस फैसले ने कई लोगों को चौंकाया है। मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि दीपिका इस फिल्म में लीड रोल नहीं निभाएंगी, बल्कि इसकी क्रिएटिव और प्रोडक्शन जिम्मेदारियां संभालेंगी। सूत्र ने कहा- 'दीपिका इस बार पर्दे के पीछे रहकर फिल्म को नए अंदाज में पेश करेंगी। उनकी जगह लीड रोल के लिए एक नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जा रहा है।' दीपिका पहले भी अपनी कंपनी केए प्रोडक्शन्स के बैनर तले फिल्मों का को-प्रोडक्शन कर चुकी हैं। इस बार वह पूरी तरह प्रोडक्शन पर फोकस कर रही हैं। आने वाले साल में वह पांच बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की तैयारी में हैं, जिनमें 'द इंटर्न' पहला होगा। उनका मकसद ऐसी कहानियां बनाना है जो दुनियाभर के दर्शकों को जोड़ सकें।'द इंटर्न' साल 2015 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है, जिसमें ऐनी हैथवे और रॉबर्ट डी नीरो लीड रोल में थे। भारतीय रीमेक का ऐलान 2020 में हुआ था। उस समय दीपिका ऐनी हैथवे वाला किरदार निभाने वाली थीं, जबकि रॉबर्ट डी नीरो के रोल में दिवंगत ऋषि कपूर नजर आने वाले थे। उनके निधन के बाद इस रोल के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया गया।

चर्चा में हंसिका मोटवानी

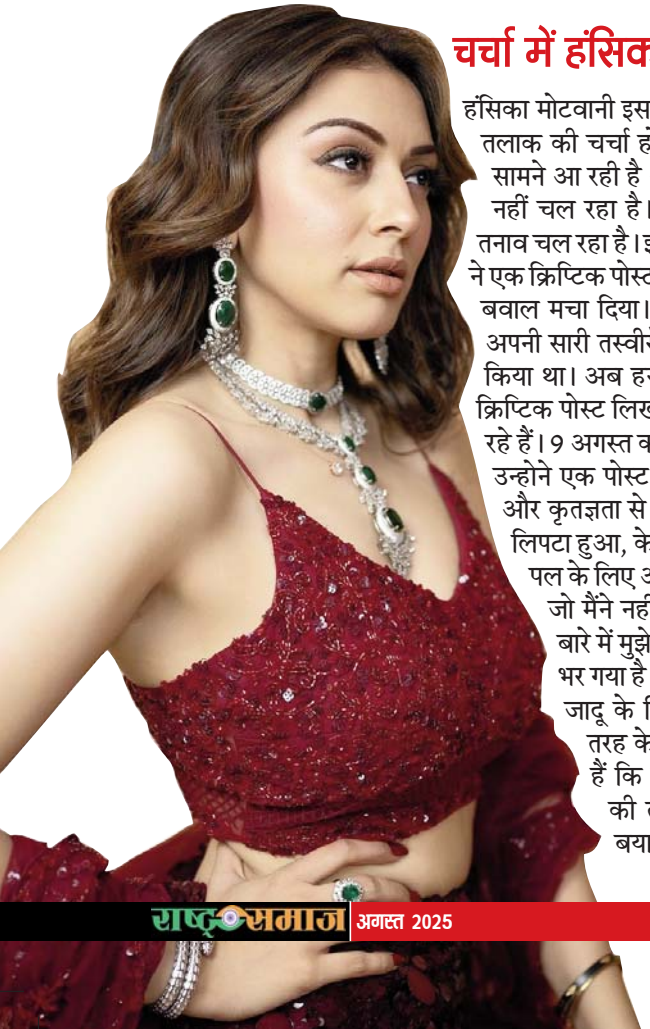

हंसिका मोटवानी इस वक्त खबरों का हिस्सा है और उनकी तलाक की चर्चा हो रही है। उनकी शादी को लेकर बातें सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनका पति सोहेल खटूरिया के साथ तनाव चल रहा है। इन बातों को हवा तब मिली जब हंसिका ने एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है और सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। इसके पहले भी उन्होने पति के साथ अपनी सारी तस्वीरों को डिलीट करके एक सवाल खड़ा किया था। अब हसीना ने अपने 34वें जन्मदिन पर एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा है जिसके लोग कई मतलब निकाल रहे हैं। 9 अगस्त को अपना जन्मदिन मनातीं हैं। इस दौरान उन्होने एक पोस्ट किया था और लिखा,'मैं बहुत विनम्र और कृतज्ञता से भरा हुआ महसूस कर रहा हूं। प्यार में लिपटा हुआ, केक से सजा हुआ, और हर छोटे से छोटे पल के लिए आभारी हूँ। इस साल मुझे वो सबक मिले जो मैंने नहीं मांगे थे... और वो ताकत भी जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। दिल भर गया है। फोन भर गया है। आत्मा को शांति मिली है। जन्मदिन के जादू के लिए शुक्रिया। इसके बाद से लोग कई तरह के कमेंट्स करते हुए ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या सबकुछ ठीक है? हालांकि दोनों की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है।

शॉर्ट्स कपड़े में दिखी शूरा

अरबाज खान की पत्नी शूरा खान उम्मीद से हैं और बहुत जल्द अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। शूरा खान प्रेग्नेंसी में खुद को पैंपर करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे रही हैं। कभी अरबाज खान के साथ तो कभी अपने दोस्तों के साथ वो मौज मस्ती और आउटिंग करती दिखाई देती हैं। अब एक बार फिर से शूरा खान का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है जिसमें उनका अलग ही बिंदास अंदाज देखने को मिल रहा है। शूरा खान इस दौरान अपनी गाड़ी से उतरकर सीधे रेस्त्रां में जाती दिखाई दीं। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने अपने बालों का काफी फ्रीकी टच दिया हुआ था। साथ ही शूरा ने इस दौरान शॉर्ट्स पहने हुए थे। इस लुक में शूरा काफी क्यूट लग रही थीं। अब हर किसी को शूरा और अरबाज खान के बच्चे का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है।

अब पानी बेचकर भरेंगी जेब भूमि पेडनेकर

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी उतर चुकी हैं। अपनी बहन समीक्षा पेडनेकर के साथ मिलकर भूमि ने लॉन्च किया है भूमि ने बताया कि बैकबे का पहला प्रोडक्ट है बैकबे पानी- नैचुरल मिनरल वाटर, जो हिमालय की गोद से सीधे आता है। इसमें प्राकृतिक तौर पर मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स मौजूद हैं। भूमि ने बताया कि उनके इस पानी की बोतल की सबसे खास बात है इसकी पैकेजिंग। जिसमें ना प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है और ना ही कांच का, बल्कि गैबल टॉप पेपर पैकेजिंग में यह पानी मिलता है। यहां तक कि इसकी कैप भी बायो-बेस्ड है।भूमि ने खुलासा किया कि उनका प्लांट हिमाचल प्रदेश में है और यह पूरी तरह उनका अपना है। साथ ही, इसमें महिलाओं के नेतृत्व वाली वर्कफोर्स काम करती है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है रोजाना 45,000 बॉक्स। वर्तमान में उनका ब्रांड दो साइज- 500टछ और 750टछ में आता है। कीमत के मामले में भी इसे खास तरीके से पोजिशन किया गया है। भूमि ने बताया कि उन्होंने इसे महंगी प्लास्टिक बोतलों और सस्ती ग्लास बोतलों के बीच रखा है। जहां बाजार में प्रीमियम प्लास्टिक बोतलें करीब 90 रुपये तक और ग्लास बोतलें 600 रुपये तक बिकती हैं, वहीं उनके ब्रांड में 500 एमएल पानी की कीमत 150 रुपये और 750 एमएल की कीमत 200 रुपये है। भूमि और समीक्षा में सिर्फ मिनरल वाटर ही नहीं, बल्कि स्पार्कलिंग वाटर भी लाने वाली हैं, वो भी तीन फ्लेवर में- लीची, पीच और लाइम।

खेसारी लाल के कृष्ण गीत ने मचाया धमाल

खेसारी लाल यादव फैन्स के पसंदीदा एक्टर हैं। हर कोई खेसारी लाल के साथ काम करना चाहता है। खेसारी अपनी आवाज के साथ ही अपने अभिनय से भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। खास बात यह है कि उनके नए के साथ ही पुराने गाने भी सोशल मीडिया पर धूम मचा देते हैं। अभी तक तो खेसारी लाल यादव के सावन के गीत सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। वहीं अब जन्माष्टमी के शुरू होने से पहले खेसारी लाल के कृष्ण गीत इंटरनेट पर छाए हुए हैं। फिलहाल तो हाल ही में खेसारी लाल यादव का एक पुराना गाना सोशल मीडिया पर फैन्स द्वारा बेहद पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह लंबे घुंघराले बालों में नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव कृष्ण की तरह हाथ में बांसुरी लिए अपने गाने को और भी मनमोहक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव के साथ ही इस गाने में प्रियंका सिंह हैं जो उनका पूरा साथ दे रही हैं। दोनों की खूबसूरत जोड़ी फैन्स का दिल जीत रही है।

51 की उम्र में बोल्ड हुईं किरण राव,

आमिर खान ने कुछ महीनों पहले ही अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से तलाक लिया है और इस वक्त गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं। एक ओर आमिर खान अपनी नई जिंदगी शुरू करने के मूड में हैं तो वहीं दूसरी ओर 52 वर्षीय किरण राव के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है।तलाक से पहले किरण राव का ऐसा लुक आपने शायद ही कभी देखा होगा। जी हां, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किरण राव को शानदार सूट में देखा जा सकता है लेकिन उनको बोल्डनेस ने लोगों को हिलाकर रख डाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि तलाक के बाद किरण राव को अब किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। उनका इतना बिंदास अंदाज शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। स्टाइलिश सूट में पोज देतीं किरण राव ने क्लीवेज फ्लॉन्ट किए हैं और बला की हॉट लग रही हैं।

एनबीसीसी ने किए 2025-26 की पहली तिमाही में अभूतपूर्व वित्तीय परिणाम दर्ज

एनबीसीसी का एकल आधार पर ई.बी.आई.टी.डी.ए. मार्जिन 5.88% तक पहुंच गया, कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) में 31.72% और कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) में 31.69% की वृद्धि हुई, जबकि समेकित आधार पर ई.बी.आई.टी.डी.ए. मार्जिन 4.61% तक पहुंच गया, कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) में 26.15% और कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) में 25.97% की वृद्धि हुई। निदेशक मंडल ने 07 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में 30.06.2025 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25की पहली तिमाही के लिए 1627.34 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए 1655.47 करोड़ रुपये की प्रचालनों से एकल आय दर्ज की। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए 2142.53 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए प्रचालनों से समेकित आय 2391.19 करोड़ रुपये रही। 30.06.2025 को समाप्त तिमाही के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर एकल आधार पर कर पूर्व लाभ (पी.बी.टी.) में 116.25 करोड़ रुपये से 153.13 करोड़ रुपये और समेकित आधार पर 143.84 करोड़ रुपये से 181.45 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर एकल आधार पर कर पश्चात लाभ (पी.ए.टी.) में 86.63 करोड़ रुपये से 114.08 करोड़ रुपये और समेकित आधार पर 107.19 करोड़ रुपये से 135.03 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।

आईएसओ 31000:2018 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली एनबीएफसी बनी

आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम व अग्रणी एनबीएफसी, को अपने उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन ढाँचे के लिए आईएसओ 31000:2018 (जोखिम प्रबंधन-दिशानिर्देश) प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि आरईसी को ब्रिटिश मानक संस्थान (बीएसआई) से यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) बनाती है। आईएसओ 31000:2018 एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है जो प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए सिद्धांत और दिशानिर्देश प्रदान करता है। जोखिम प्रबंधन और न्यूनीकरण के मोर्चे पर आरईसी को महत्वपूर्ण मूल्य प्रदान करने हेतु सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के हमारे प्रयासों का प्रमाण है। आरईसी के मुख्य जोखिम अधिकारी, सुब्रत ऐच ने कहा,यह आईएसओ 31000:2018 प्रमाणन उद्यम जोखिम प्रबंधन में उत्कृष्टता के प्रति आरईसी की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आरईसी का जोखिम प्रबंधन के प्रति एक संरचित, व्यापक व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण है, जो निवेशकों व ऋणदाताओं सहित हमारे सभी हितधारकों के विश्वास को और बढ़ाएगा।

एचपीसीएल ने किया अड्नोक गैस के साथ 10 वर्षीय एलएनजी खरीद अनुबंध

अनुबंध से बढ़ते भारतीय गैस बाजार में एचपीसीएल की स्थिति एक प्रमुख और विश्वसनीय प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता के रूप में मजबूत होगी । भारत की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधक और विपणन कंपनियों में से एक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने अड्नोक गैस की सहायक कंपनी अबू धाबी गैस लिक्विफिकेशन कंपनी (एएलएनजी) के साथ 10 साल की अवधि के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस की खरीद हेतु एक अनुबंध शीर्ष (एचओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। अड्नोक गैस एक विश्वस्तरीय, बृहद पैमाने पर एकीकृत गैस परिचालन और बिक्री कंपनी है जो गैस मूल्य श्रृंखला में कार्यरत है।

एचओए के नियमों के तहत, एचपीसीएल अपनी रिफाइनरियों, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मांग को पूरा करने और डाउनस्ट्रीम ग्राहकों के बीच खपत के लिए हाल ही में चालू किए गए छारा एलएनजी टर्मिनल, गुजरात से एलएनजी प्राप्त करेगी। इस पहल से एचपीसीएल एलएनजी हासिल करने और प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक एलएनजी अनुबंधों सहित एक विविध पोर्टफोलियो बनाने में सक्षम होगा।

इस अनुबंध के अंतर्गत की जाने वाली आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के प्रति एचपीसीएल की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यह रणनीतिक साझेदारी भारत की अपनी ऊर्जा क्षमता में गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस तरह के दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध अत्यधिक अस्थिर वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के बीच विश्वसनीयता, सामर्थ्य और आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एन बी सी सी
NBCC
A Navratna CPSE

NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CHANGING BUILDING LANDSCAPE FOR SUSTAINABLE FUTURE

DOMESTIC PROJECTS

AIIMS DEOGHAR
AT JHARKHAND

BHARAT MANDAPAM
AT NEW DELHI

AMRAPALI PROJECTS
AT NOIDA & GREATER NOIDA

VANIJYA BHAWAN
AT NEW DELHI

DHANA DHANAYE AUDITORIUM
AT KOLKATA

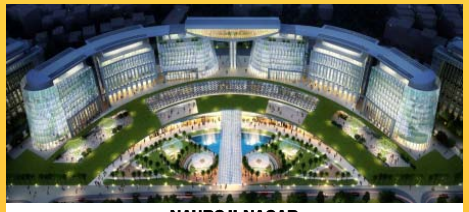

NAUROJI NAGAR
AT NEW DELHI

SUPER THERMAL POWER PROJECT
AT NAGPUR, MAHARASHTRA

ILLUMINATION OF LAL QUILA
AT DELHI

BORDER FENCING FROM HARI NAGAR
TO SUTARKANDI AT ASSAM

OVERSEAS PROJECTS

MAHATMA GANDHI INTERNATIONAL CONFERENCE
CENTRE AT NIAMEY, NIGER

INDIAN PAVILION
AT WORLD EXPO 2020

INSTITUTE FOR SECURITY & LAW ENFORCEMENT
STUDIES AT ADDU CITY

NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003 I CIN-L74899DL1960GOI003335 I www.nbccindia.in

Follow us on /officialNBCC @officialNBCC

Innovation & Excellence At Work

RNI No.: DELHIN/2014/56304

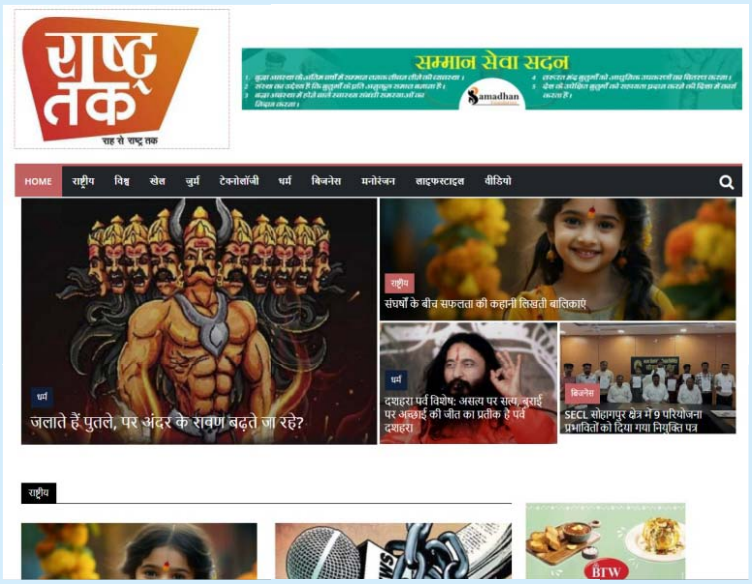

राष्ट्रीय | खेल | विश्व | जुर्म | टेक्नोलॉजी | बिजनेस | धर्म | और भी बहुत कुछ

पढ़ें

अपनी पसंदीदा खबरें

rashtratak.com पर

राष्ट्र तक
राह से राष्ट्र तक

राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका
राष्ट्र समाज
आपकी आवाज़

Samadhan Foundation

for news coverage and programsplease contact us on below Mobile No.
9953772767,9911662767

https://twitter.com/rashtratak https://www.facebook.com/rashtrataknews

rashtratak@gmail.com
www.rashtrasamaj.com

A Digital News Paltform of
RASTRA SAMJA